आज़ादी का अमृत महोत्सव

संसद में सुशील कुमार मोदी

(बजट सत्र 2022-23)

महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर भाषण एवं हस्तक्षेप

विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित लेख

Aatma Nirbhar Bharat Ka Budget brings with it new energy and strength to our development trajectory, especially at a time when we are courageously fighting a once-in-a-lifetime global pandemic. This Budget brings more infra, more investment, more growth and more jobs.

- Narendra Modi

अनुक्रमणिका

1.	राज्यसभा में बजट, 2022–23 पर भाषण	1–11
2.	Appropriation Bill एवं Finance Bill, 2022 पर भाषण	12–24
3.	The Chartered Accountants, The Cost & Works Accountants and The company Secretaries Bill, 2021 पर भाषण	25–29
4.	केन्द्रीय विद्यालय में सांसद कोटा समाप्त करने सम्बन्धी प्रश्न	30–33
5.	**विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित मेरे लेख**	
	I) A Quota Too Many	34–37
	II) Why discretionary quotas in KVs are inherently unfair	38–40
	III) For a United States of GST	41–43
6.	Demand For Investigation of Cases of Bank Fraud Amounting To Rs. 13,000 Crore	44–45
7.	Demand For 'One Nation One Tariff' For Power In India	46–47
8.	रेलवे के ग्रुप 'डी' और NTPC परीक्षार्थियों से जुड़ा मुद्दा	48–50
9.	Demand For Timely Local Body Elections With Reservations For OBCs	51
10.	Demand For Evolving National Policy To Facilitate Retail Traders	52
11.	Demand For High Level Inquiry To Investigate Atrocities Against Pandits In Kashmir	53–54
12.	Demand For Bringing Crypto Assets Under G.S.T.	55–56
13.	Marital Rape संबंधी पूछा गया पूरक प्रश्न	57
14.	Websites पर महिलाओं के अश्लील चित्र डालने से जुड़ा मुद्दा	58
15.	बरौनी खाद कारखाना चालू कराने से जुड़ा मुद्दा	59–60
16.	माँ जानकी के जन्म स्थान पुनौरा धाम से जुड़ा मुद्दा	61
17.	भारत में बाघों की मृत्यु से जुड़ा मुद्दा	62–63

राज्यसभा में बजट, 2022–23
पर
भाषण

Shri Sushil Kumar Modi (BIHAR) : Sir, Smt. Nirmala Sitharamanji is an alumnus of JNU. She does not have a degree from Harvard Business School, जो डिग्री चिदम्बरम साहब के पास है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि in comparison to global financial crisis और Taper Tantrum 2012-13 के समय कांग्रेस ने जो बजट पेश किया था, she has presented 100 times better Budget in such adverse conditions.

महोदय, Spanish flu 1917-18 में आया था, तब भारत में 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। उस समय भारत की आबादी 30 करोड़ थी और 1.5 करोड़ लोग मरे थे।

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : महोदय, इस कोविड काल में भारत में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, जो अत्यंत दुःखद है, लेकिन महोदय, अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है, which is one-fourth of india, and 9,26,000 people died. Brazil has a population of only 21 crore, which is one-seventh of India, but 6,32,000 people died there; Russia's population is one-tenth of India, but 3,35,000 people died there; UK has twenty times less population than India, but two lakh people died there. अगर नरेन्द्र मोदी जी का नेतृत्व नहीं होता और फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज़ का सहयोग नहीं होता, तो इस देश में 5 लाख नहीं, 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए होते। हमारे पास अमरीका, यू.के., फ्रांस, ब्राजील जैसी हेल्थ की सुविधा नहीं है, फिर भी हमने इस देश के 40–45 लाख लोगों को मरने से बचा लिया, नहीं तो कितने लोग मरते कहना मुश्किल है। किसी ने ठीक ही कहा है,

''वसुधा का नेता कौन हुआ?
भूखंड-विजेता कौन हुआ?
अतुलित यश क्रेता कौन हुआ?
नव-धर्म प्रणेता कौन हुआ?
जिसने न कभी आराम किया,
विघ्नों में रह कर काम किया।।''

ये थे माननीय नरेन्द्र मोदी, जिन्होंने विकट परिस्थितियों में देश को नेतृत्व प्रदान किया। आप मज़ाक उड़ाते हैं कि ये लोग फेल हो गए। महोदय, भारत में अब तक 170 करोड़ वैक्सींस लगाई जा चुकी हैं, वहीं अमरीका में 53 करोड़, ब्राजील में 36 करोड़, जर्मनी में 16 करोड़, रशिया में 15 करोड़ और यू.के. में 13 करोड़ वैक्सींस लगाई गई हैं।

महोदय, यह जो वैक्सीन है, यह Made in India, Made by India है। अगर भारत में वैक्सीन नहीं बनी होती, तो 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए हमें दुनिया के सामने जा कर भीख मांगनी पड़ती कि हमें वैक्सीन दे दीजिए। वर्षों लग जाते, तो भी हम देश के 140 करोड़ लोगों तक वैक्सीन नही पहुँचा पाते।

महोदय, हमने CoWIN का tech platform develop किया, हमने लोगों को QR-coded certificate प्रदान किए, एक लाख cold-chains स्थापित किए और last mile delivery तक वैक्सीन को पहुँचाने का काम किया। महोदय, दुनिया में केवल सात देश हैं, जो वैक्सीन बनाते हैं- USA, China, France, U.K., Russia, Canada और 7वाँ देश भारत है। आज African continent का क्या हाल है? वहां केवल 16 प्रतिशत लोगों को first dose लगी है और केवल 11 प्रतिशत लोगों को second dose लगी है। इतना ही नहीं, भारत ने 150 से ज्यादा देशों को Covid-19 related medical and other assistance देने का काम किया है। 28 जनवरी, 2022 तक हमने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को 14 करोड़, 63 लाख doses vaccine मुफ्त देने या commercial export करने का काम किया है।

महोदय, ये नरेन्द्र मोदी जी ही हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होते। दिनकर ने ठीक ही कहा,

''सच है, विपति जब आती है,
कायर को ही दहलाती है,
सूरमा नहीं विचलित होते,
क्षण एक नहीं धीरज खोते,
विघ्नों को गले लगाते हैं,
कांटों में राह बनाते हैं।।''

यह नरेन्द्र मोदी जी की ताकत है कि कोरोना काल का भारत ने मजबूती से मुकाबला किया है। महोदय, मैं कल से कांग्रेस के नेताओं का रोजगार के संबंध में भाषण सुन रहा हूँ, पता नहीं उन्होंने अपने शासन के 50 सालों में कितना रोजगार पैदा किया, लेकिन इस बजट का अगर कोई एक फोकस है, that is, 'job, job and job' 'रोज़गार, रोज़गार, रोज़गार।' इसके हरेक पन्ने पर रोज़गार लिखा है, इसके हरेक पन्ने से रोजगार पैदा होता है। महोदय, हम देश को ऐसा विकास दे रहे हैं, जो रोज़गार पैदा करने वाला विकास है, job-oriented growth है, growth with job creation है। महोदय, रोज़गार लोगों को dole देने से पैदा नहीं होता है।

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : कैश ट्रांसफर देने से income support से रोजगार पैदा नहीं होता है। हमने भी income support दिया है, हमने भी Corona काल में लोगों की मदद की है, लेकिन अगर रोजगार पैदा होता है तो Capital Expenditure से पैदा होता है, अगर रोजगार पैदा होता है तो Manufacturing से होता है। किसी ने ठीक ही कहा –

''न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है,
अभी तो सफर शुरू किया है,
न हारूंगा हौसला उम्र भर,
मैंने किसी से नहीं, खुद से वादा किया है।''

श्री नरेन्द्र मोदी ने केवल जनता से नहीं, खुद से वादा किया है।

महोदय, Capital Expenditure का जिक्र हो रहा है। पिछले चार सालों में India would be spending, if you include 2023, Rs. 20 lakh crore. इस साल को मिलाकर पिछले चार सालों में हम बीस लाख करोड़ रूपये Capital Expenditure पर खर्च करने जा रहे हैं या खर्च कर चुके हैं। आज तक आज़ाद भारत का इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी नहीं हुआ था। इसलिए इस साल के बजट में Capital Expenditure Rs. 7,50,000 crore; का प्रावधान किया गया है। the outlays have been increased by 35 percent. 1 लाख करोड़ Capital Expenditure through grant-in-aid to States, अगर उसे जोड़ लें तो effective Capital Expenditure is Rs. 10,68,000 crore which is

4.1 percent of the GDP. Capital Expenditure का multiplier effect होता है। If Revenue Expenditure increases by Rs. 100, then, only Rs. 98 is added to economy but if you spend Rs. 100 as Capital Expenditure, Rs.245 is added to the economy in the same year और बाद के वर्षों में 480 रूपये इकोनॉमी के अंदर ऐड होते हैं। Capital Expenditure demand भी create करेगा, supply side को भी देखेगा। It would crowd in private investment. There would be huge job creation. Contractor, Supplier, Skilled technicians, Cement, Steel, Sand आदि हर चीज की डिमांड बढेगी।

महोदय, एक लाख करोड़ रूपये सरकार ने राज्यों को Capital Expenditure के लिए दिये और वह भी 50 years' interest-free loan. कांग्रेस ने कभी राज्यों को 50 साल के लिए interest-free लोन Capital Expenditure के लिए दिया था? In road sector, we would be spending Rs. 2,42,000 crore. That is the highest ever expenditure in the road sector and we would be building 25,000 K.M. National Highways in the year 2023.

महोदय, इस बार के road के Budget में हमने कोई borrowing नहीं की है। इसके पहले 65 हजार करोड़ हमने नेशनल हाइवे के लिए Borrowing की थी and this year we have supported the National Highway with the Budgetary support. They would not be taking a single penny as a borrowing. केवल road sector ही नहीं, अन्य Sector में भी बड़े पैमाने पर Capital Expenditure कर रहे हैं, Defence पर Rs. 1,52,000 crore, Railway पर Rs. 1,37,000 crore, Telecom पर Rs. 54,150 crore, Metro पर Rs. 19,130 crore, Atomic energy पर 1.9 per cent of Capital Expenditure. अगर इससे रोजगार पैदा नहीं होंगे, तो किससे रोजगार पैदा होंगे, आप ही बता दीजिए कि कैसे रोजगार पैदा होते है?

महोदय, 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' के लिए 2021-22 का Rs. 14,000 crore का Budget था, there has been a 27 per cent

increase in the P.M. Gram Sadak Yojana to Rs. 19,000 crore. क्या 'प्रधान मंत्री सड़क योजना' से रोजगार पैदा नहीं होगा? 'नल जल योजना' से हम 3.8 crore घरों में Rs. 60,000 crore रूपये खर्च करके अगर tap water supply पहुँचायेंगे तो क्या jobs create नहीं होगा? अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए Rs. 48,000 crore खर्च कर रहे हैं, तो क्या इससे रोजगार पैदा नहीं होगा?

महोदय, मुझे बहुत हंसी आती है और दुःख भी होता है कि चिदम्बरम साहब और कपिल सिब्बल जी जैसे लोग R.E. से B.E. से तुलना कर रहे हैं। They are comparing Revised Estimates with the Budget Estimates.

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : चिदम्बरम साहब, आप तो कई बार वित्त मंत्री रह चुके हैं, इतना तो आपको मालूम है कि हमेशा Budget Estimates को Budget Estimates से compare करते हैं न कि Revised Estimate से। अगर 'मनरेगा' में पिछली बार 72,000 करोड़ रूपये थे और बाद में हमने इन्क्रीज किया। इस बार भी बजट में उतना ही रखा, जितना पिछली बार था। Now, you are comparing the Budget Estimate of 2022-23 with the Revised Estimate of 2021-22.

महोदय, 2020 से 2025 तक 111 लाख करोड़ रूपए we will be spending on the NATIONAL INFRASTRUCTURE PIPELINE (NIP). It will be a world-class infrastructure.

महोदय, इतना ही नहीं **'प्रधान मंत्री गति शक्ति'**, जो कि रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, mass transport, waterways, logistics के projects pertaining to seven engines of growth in the NIP will be aligned with the PM Gati Shakti Programme. पीएम गति शक्ति और एनआइपी, इन दोनों को align किया गया है। multi-model connectivity, world-class modern infrastructure and logistic synergy among different modes of movement.

आप मेन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। Productivity-Linked Incentive Scheme, के अन्तर्गत 14 सेक्टर्स में 30 लाख करोड़ से ज्यादा का एडिश्नल प्रोडक्शन अगले 5 साल में करेंगे and Rs. 3,46,000 crore

will be spent as a incentive to the industries in 14 sectors. 76 हजार करोड़ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, as an incentive, खर्च करने वाले हैं। हमारे देश के अंदर सोलर PVS नहीं हैं। सोलर प्लेट्स को चाइना से इम्पोर्ट करना पड़ता है। हम निर्मला जी और प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद देंगे कि this year she has increased from Rs. 4,500 Crore to additional Rs. 19,500 crore for manufacturing of solar panels. Sir, there will be 280 GW of installed solar capacity by the year 2030. हम वर्ष 2030 तक 280 गीगावॉट सोलर कैपेसिटी पैदा करेंगे।

महोदय, चाहे सेमीकंडक्टर्स हों, ऑटो कंपनीज़ हो, automobiles हों, इलेक्ट्रोनिक्स हों, कैमिकल्स हों, फॉर्मा हों, medical devices हों, फूड प्रोसेसिंग हो, टेलीकॉम हो, textile हो white goods हों, drones हो, इन पर हम इतनी बड़ी राशि खर्च करने जा रहे हैं और आप कहते हैं कि रोजगार कहाँ से पैदा होगा? माननीय उपसभाध्यक्ष जी, नरेन्द्र मोदी जी लम्बे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनको मालूम है। जैसा किसी ने कहा–

'हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है,
हम जहाँ से जायेंगे, वह रास्ता बन जाएगा।
अगर देखना चाहते ये मेरी उड़ान को,
(अगर नरेन्द्र मोदी की उड़ान को देखना चाहते हो)
तो जाओ उंचा करो आसमान को'।

आप आसमान को जितना उंचा कर सकते हो, करो, हम अपना हुनर दिखायेंगे।

उपसभाध्यक्ष जी, ये जमाना metaverse का है, web-3, artificial intelligence का जमाना है और आप कहते हैं कि डिजिटल से क्या होगा? कपिल सिब्बल जी, आप तो कम से कम इस तरह की बात मत किजिए। दुनिया में अभी तक 9 देश हैं, जिन्होंने डिजिटल करेंसी लॉंच की है, and all these countries are nation islands, Bahamas जैसे छोटे–छोटे देश हैं, जिनकी आबादी 4 लाख या 5 लाख होगी, उन्होंने डिजिटल करेंसी लॉंच की है।

India will be the tenth country in this world which will be launching digital currency. इससे transparency in transaction, reducing use of black money, cheaper currency management, more secure and risk-free online payment, inter-bank settlement not required and handling, printing, logistics management of cash आसान होगा और आप इसका मज़ाक उड़ा रहे हैं? महोदय, क्या बिना digitization, के आप दुनिया की प्रगति की दौड़ में survive कर सकते हैं?

बजट में घोषणा की गई है कि 75 जिलों के अंदर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित किए जायेंगे। 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' और डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। High Speed Optic Fibre वर्ष 2025 तक देश के सभी गाँवों तक पहुँचा दिये जायेंगे। Sir, E-Passports, National Tele Mental Health Programme, Animation, Visual Effects, Gaming and Comics, इसके task force का गठन किया जाएगा, जिसमें 20 लाख जॉब्स का पोटेंशियल है।

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : सर, अभी यादव जी कह रहे थे कि किसान ड्रोन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि for spraying of insecticides, for crops assessment; the Government will use these things और जो प्रगतिशील किसान हैं, वे ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे।

सर, चिदम्बरम जी और कपिल सिब्बल जी कह रहे थे कि चैनल्स से क्या होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप कभी गाँव में रहे ही नहीं। बिहार के हर घर तक बिजली पहुँच चुकी है। देश का एक भी गरीब नहीं होगा, जिसके घर में बिजली नहीं पहुँची होगी और आप कहते हैं कि टीवी नहीं है! महोदय, केवल बिहार में दो करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हो गए। हमारी सरकार ने तय किया है और कहा है कि हम पहली क्लास से बारहवीं क्लास तक के लिए 12 की बजाए 200 चैनल्स launch करने जा रहे हैं।

महोदय, post office कल तक केवल letter और money order पहुँचाने का काम करते थे। अभी तक 20,000 post offices have been converted into core banking and Government has decided

that in the coming years, more than 1,50,000 post offices will be converted into core banking.

सरकार digital payment को प्रमोट करेगी and there will be world class foreign university. जब इतना डेटा पैदा होगा, data explosion होगा, तो हमें data centre की आवश्यकता पड़ेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी तय किया है कि contractors, suppliers का जो बिल होगा, उसका 75 per cent bill will be paid within ten days और यह e-bill system में होगा। Everything will be submitted online. There will be digitally signed bills.

महोदय, यह नरेन्द्र मोदी जी ही हैं, जो मुश्किलों से भागते नहीं है। किसी ने कहा है :

'' मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है,
हर पहलू जिन्दगी का इम्तिहान होता है।
डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिन्दगी में,
लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है।''

ऐसे लोगों के कदमों में जहाना होता है, पूरी दुनिया उनके कदमों में होती है।

महोदय, अब मैं टेलीकॉम के संबंध में कहना चाहता हूँ। सिब्बल साहब तो टेलीकॉम मिनिस्टर भी थे। हम 5G launch करने जा रहे हैं। इस साल उसका auction हो जाएगा और साल का अंत होते-होते हम 5G launch कर देंगे। Do you know the speed of 5G? It will be having 10,000 to 30,000 megabytes per second. 4G की स्पीड कितनी है? 4G की स्पीड 100 से 300 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड है। इतना ही नहीं, 5G के auction से एक लाख करोड़ रूपए मिलेंगे। हम लोगों ने सितम्बर, 2021 में Telecom Reforms Package की घोषणा की थी, जिससे वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस इंडस्ट्री के रेवेन्यू में 30,000 करोड़ रूपए की वृद्वि होगी।

महोदय, हमने बीएसएनएल को 2019 में पैकेज दिया था। सरकार ने बीएसएनएल को 45,000 करोड़ रूपए का capital outlay provide किया है। बीएसएनएल को भी इस साल 4जी में convert करेंगे। सरकार केवल 5जी ही नहीं ला रही है, बल्कि आज 6जी को लेकर meeting है, यानी भारत अभी से 6जी की तैयारी कर रहा है कि 6 जी का standard क्या होगा।

महोदय, जब से Direct Benefit Transfer Scheme launch हुई है, तब से अभी तक सरकार 21 लाख करोड़ रूपए beneficiaries के खाते में पहुँचा चुकी है। इससे 2,22,000 करोड़ रूपए की सेविंग हुई है। भारत सरकार को केवल Direct Benefit Transfer Scheme के द्वारा 2,22,000 करोड़ रूपए की बचत हुई है। इसके लागू होने से चार करोड़ डुप्लिकेट राशन कार्ड्स रद्द कर दिए गए, चार करोड़ से ज्यादा एलपीजी के fake connections खत्म कर दिए गए, reduction of 120 lakh matric tonnes of fertilizer sale to retailers में मदद मिली है।

महोदय, 2014 में जब नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने, तब मोबाइल फोन की केवल दो मैन्युफेक्चरिंग यूनिट्स थी और 2020-21 में, 200 manufacturing units of mobile phones are in India. 2014-15 में जहाँ हम 6 करोड़ मोबाइल्स तैयार कर रहे थे, 2020-21 में, we have manufactured more than 30 crore of mobile phones in this country itself.

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : And, in Unified Payment Interface, हमने यूपीआई के द्वारा एक साल में Rs. 3,874 crores ट्रांजेक्शंस किए हैं, जिनकी value 72 लाख करोड़ है।

महोदय, कल प्रधान मंत्री महोदय स्टार्टअप्स का जिक्र कर रहे थे। Unicorn उसे कहते हैं, जिसकी value सात हजार करोड़ से ज्यादा होती है। महोदय in the year 2021 during pandemic, 44 Startups have reached the status of unicorn in a single year. 14 जनवरी, 2021 तक 83 unicorns with a total value of 277 billion dollars, यानी 83 unicorns की value सात हजार करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। आज इंडिया, यूएसए और चाइना के बाद, Unicorns और Startups के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। मैं सदन को यह भी बताना चाहूँगा कि Rupees five lakh fifty thousand crores were invested by venture capital and private equity in the startup ecosystem which in one of the largest in this world.

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह सरकार इतना काम कर रही है। किसी ने कहा हैः-

''मंजिल उन्हीं को मिलती हैं,
जिनके सपनों में जान होती है,
पंख से कुछ नहीं होता है,
हौसलों से उड़ान होती है।''

महोदय, चाइना, जापान और स्विट्ज़रलैंड के बाद आज इंडिया के पास world में highest Foreign Exchange Reserve है। We have the highest FDI inflow. यह Covid disruption के बाद highest FDI inflow in this country है। In exports, हम 3,00 billion export merchandise का आँकड़ा cross कर चुके हैं and, for the first time, हम 4,00 billion export merchandise का आँकड़ा पार करेंगे। जीएसटी के अंदर record revenue collection Rupees one lakh forty thousand crores और यह pandemic के बावजूद हुआ है । इस पूरे financial year में हमने record revenue collection किया है।

महोदय, 'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान), के तहत अभी तक 86 लाख लोगों ने 'उड़ान' का इस्तेमाल किया है। अगर 'उड़ान' योजना नहीं होती, तो गरीब, चप्पल वाले लोग 'उड़ान' का इस्तेमाल नहीं कर पाते ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : सुशील कुमार मोदी जी, आप wind up कीजिए। **....** (समय की घंटी)**....**

श्री सुशील कुमार मोदी : सर, मैं दो मिनट और लूँगा।

In IPOs, in the year 2021-22, so far Rs. 89,066 crore has been raised by 75 IPOs. जो पिछले दस साल का highest है।

अंत में, मैं बताना चाहूँगा कि 25th January को International Monetary Fund की World Economic Outlook Report आई है। Report के अनुसार India's real GDP is projected to grow at 9 per cent in both 2021-22 and 2022-23 and at 7.1 per cent in 2023-24. This projects India as the fastest-growing major economy in the world in all these three years. इन तीन सालों के अंदर भारत दुनिया के सबसे ज्यादा तेज गति से विकास करने वाले देशों में होगा।

महोदय, India Today का Mood of the Nation Survey आया है। यह हमारा survey नहीं है, India Today Magazine का survey है और वे कहते हैं कि 68 per cent people are satisfied with the performance of the Narendra Modi Government. यह pandemic के बावजूद है। महोदय, मैं एक मिनट और लूँगा। एक International global consulting firm है, उसने सर्वे किया। चार दिन पहले mint में आया है कि 'नमो' की popularity 72 per cent है, Mexico के President की popularity 64 per cent है, Italian PM की popularity 57 per cent है, जापान 47 per cent और Joe Biden केवल 41 परसेंट पर हैं।

श्री सुशील कुमार मोदी, (क्रमागत) : महोदय, मैं अंत में यही कहूँगा :

''लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती,
हौसले बुलंद हों तो दीवार नहीं होती,
जलते हुए चिराग ने आँधियों से यह कहा,
उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती।''

उपसभाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं निर्मला जी को इस बजट के लिए धन्यवाद देता हूँ।

Appropriation Bill एवं Finance Bill, 2022
पर
भाषण

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : माननीय उप सभापति महोदय, मैं एप्रोप्रिएशन बिल, 2022-23 और फाइनेंस बिल, 2022-23 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज से ठीक दो वर्ष पूर्व 24 मार्च, 2020 को इस देश में लॉकलाडन लागू किया गया था।

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : COVID के दौरान National Disaster Management ACt, 2005 invoke किया गया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है। पिछले 2 सालों में देश को एक लम्बे समय तक lockdown से गुजरना पड़ा, देश के लाखों मजदूरों को, चूँकि उनकी फैक्टरियाँ बन्द हो गयी थीं, उनकों ट्रेनों में बैठ कर अपने-अपने गाँव लौटना पड़ा। इस संकट के दौर से पूरे देश को गुजरना पड़ा। तरह-तरह की बंदिशें लगायी गयीं। महोदय, इस lockdown के खिलाफ यद्यपि विपक्ष के लोगों ने गरीबों को भड़काने का प्रयास किया, लेकिन पूरे हिन्दुस्तान में एक भी जगह कोई धरना, प्रदर्शन या बन्द नहीं हुआ। एक भी नागरिक या मजदूर lockdown के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरा।

महोदय, इसके बाद टीकाकरण प्रारम्भ हुआ। टीकाकारण का मज़ाक उड़ाया गया। अभी तक 181.56 करोड़ डोज टीका लग चुका है। शुरू में hesitancy थी, लोगों में संशय था, लेकिन टीके के विरोध में कहीं कोई सड़कों पर नहीं आया। महोदय, फ्रांस, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, आस्ट्रेलिया और जर्मनी में हजारों लोग vaccination के विरोध में सड़कों पर आ गये। Lockdown के विरोध में न्यूजीलैंड के अन्दर 40,000 लोग सड़कों पर आयें। उनको गिरफ्तार करना पड़ा, लाठी चार्ज करना पड़ा। महोदय, अगर आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने कठोर Lockdown लागू नहीं किया होता और जिस तरह से टीकाकरण का काम चालू किया, अगर वह नहीं किया होता, तो देश के अन्दर 5 लाख नहीं, बल्कि 50 लाख लोग मरे होते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 45 लाख और लोगों को मरने से बचा लिया।

उप सभापति महोदय, बिल गेट्स Microsoft के Chief Executive एवं MD हैं, उन्होंने भारत के बारे में कहा कि 'India has delivered over sixteen crore doses of Covid-19 vaccines to nearly 100 countries. Thanks to Indian manufacturers." आपने धन्यवाद दिया या नहीं दिया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के CEO बिल गेट्स ने भारत की सरकार और manufacturers को धन्यवाद दिया।

महोदय, मैं lockdown का जिक्र कर रहा था। आप कनाडा के बारे में जानते हैं! कनाडा के अन्दर, Freedom Convoy-22, के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय Ambassador Bridge जो कनाडा और अमेरिका को जोड़ता था, वहाँ के truckers ने उसको एक महीने से ज्यादा समय तक जाम कर दिया। 21 दिनों तक 12-12 घंटे हॉर्न बजाकर कोविड के प्रतिबंधों एवं टीकाकरण का विरोध करते रहे। कनाडा में ऐसे हालात पैदा हो गये कि वहाँ के प्रधानमंत्री को अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर अज्ञात स्थान पर जाना पड़ा। महोदय, फिर भी जब turckers को vaccination के खिलाफ रोक नहीं पाये, तो उनको emergency लगानी पड़ी। कनाडा के इतिहास में यह पहली घटना है कि vaccination के विरोध में जो लोग सड़कों पर आये थे, उनको रोकने के लिए सरकार को emergency लागू करनी पड़ी।

महोदय, यह था कनाडा, यह था यूरोप। लेकिन ये वही Canadian Prime Minister हैं, जो भारत के अन्दर किसान आन्दोलन के समर्थन में बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि मैं शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ हूँ, लेकिन जब अपने देश के अन्दर ट्रकवालों की हड़ताल हुई, तो कहते हैं कि यह तुरत बन्द होना चाहिए। ये वही व्यक्ति हैं, जिसने emergency लगायी, हजारों लोगों को पकड़कर जेलों के अन्दर बन्द कर दिया। महोदय, इस देश के प्रधान मंत्री के प्रति लोगों का जो भरोसा था, यह उसी का परिणाम था कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नहीं आया, किसी ने विरोध नहीं किया, चाहे वह टीकाकरण हो या lockdown हो। हमने सफलतापूर्वक Covid-19 का मुकाबला किया है।

महोदय, यहाँ बार-बार सरकार पर पूँजीपतियों को संरक्षण देने का आरोप लगता रहता है। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूँ कि अगर 19 महीनों तक इस देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज प्रतिमाह मुफ्त दिया गया, तो क्या वह अनाज अम्बानी और अडाणी के खाते में गया या इस देश के 80 करोड़ लोगों के घरों के अन्दर गया?

महोदय, अभी तक 2 लाख, 68 हजार करोड़ रूपए का अनाज वितरित किया जा चुका है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 2 दिन पहले यह निर्णय लिया गया है कि मुफ्त अनाज वितरण को 6 महीनें के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : 80 करोड़ लोगों को छह महीने तक अनाज देंगे, उससे 80 हजार करोड़ रूपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिसका हम बजट में प्रावधान करेंगे, लेकिन किसी गरीब को भूखे नहीं मरने देंगे। हम किसी गरीब को भूखा नहीं सोने देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा, world's largest food security कार्यक्रम सरकार लागू कर रही हैं।

महोदय, हम 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की बात करने वाले लोग है। यूक्रेन संकट के दौरान केवल भारत के 20,000 लोगों को ही evacuate करने का काम नहीं किया, बल्कि हमनें 18 देशों के 150 से ज्यादा नागरिकों को यूक्रेन से निकालने का काम किया है। हमारी सरकार ने यूक्रेन, पौलैंड, रोमानिया, स्लोवाक रिपब्लिक जैसे देशों को 90 टन relief material भी देने का काम किया है। महोदय, अफगानिस्तान से हमारे राजनयिक संबंध नहीं है, फिर भी हमने 50,000 मेट्रिक गेहूँ देने का एलान किया है। हम 5 लाख डोज़ वैक्सीन दे चुके हैं और 13 टन life-saving medicines दे रहे हैं। महोदय, हमारे बगल का पड़ोसी देश श्रीलंका भंयकर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। हमने अन्य पड़ोसी देशों के साथ श्रीलंका की भी चिंता की और 1 billion dollar यानि लगभग सात हजार करोड़ रूपए का credit line श्रीलंका को उपलब्ध कराया, ताकि वह essential commodities, food, medicines आदि भारत से खरीद सके। अब तक कुल 2.4 billion dollar यानी करीब 16 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा की आर्थिक मदद क्रेडिट के रूप में हमने श्रीलंका को देने का काम किया है।

महोदय, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने record direct tax collection किया है, जिसमें Corporate Tax और Income Tax दोनों शामिल हैं। Budget Estimate 11.08 लाख करोड़ का था, जिसे Revised Estimate में 12.5 लाख करोड़ किया गया और हम अभी तक target से 1 लाख, 1 हजार करोड़ रूपए ज्यादा संग्रह कर चुके हैं और 31 तारीख आते-आते हम रिकॉर्ड संग्रह करने में सफल होंगे। सरकार ने 13 लाख, 63 हजार करोड़ रूपए संग्रह किया, यह वर्ष 2020-21 से 38 परसेंट ज्यादा है। 2019-20 से 36.6 परसेंट ज्यादा है और वर्ष 2018-19 की Pre-pandemic period से 32.7 परसेंट ज्यादा है। इसका मतलब है कि अब आर्थिक विकास की गाड़ी धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है।

महोदय, बार-बार जीएसटी की चर्चा होती है। सदन को यह ज्ञात है कि हम अभी तक 13 लाख, 41 हजार करोड़ रूपए जीएसटी संग्रह कर चुके हैं। एक साल में पाँचवीं बार हमने 1 लाख, 30 हजार करोड़ के target को क्रॉस किया है। यानि पाँच महीने ऐसे हैं, जहाँ प्रतिमाह हमने 1 लाख, 30 हजार करोड़ रूपए संग्रह किए गए हैं।

महोदय, एक बड़ी चुनौती पूरे देश और सारे राज्यों के सामने है क्योंकि पाँच साल के लिए compensation का वायदा किया गया था, उसकी अवधि 31 जून को पूरी हो रही है। 1 जूलाई, 2022 के बाद compensation नहीं मिलेगा। राज्यों को प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ रूपए से ज्यादा का नुकसान होगा। आखिर वह कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? 5 साल के लिए compensation assure किया गया था कि प्रतिवर्ष 14 परसेंट की year-on-year growth provide करेंगे और यदि 14 परसेंट से कम की growth होगी, तो बीच का gap है, उसे compensation से provide किया जाएगा।

सरकार ने यह भी कहा था कि compensation खजाने से नहीं देंगे। अलग से एक Compensation Fund Create किया जाएगा। कोयला, पान, मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लक्ज़री गाड़ियों पर 28 परसेंट जीएसटी के उपर cess लगयाा गया। over and above 28 परसेंट और उससे जो

राशि आएगी, उसे Compensation Fund में रखा गया तथा उससे राज्यों के क्षतिपूर्ति की भरपाई की जा रही थी। जब 30 जून को compensation period समाप्त हो जाएगा, तो आगे क्या होगा?

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है कि compensation cess को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया जाए। भारत सरकार ने कोरोना काल में राज्यों को लोन लेकर compensation provide किया है। चूँकि सेस में इतना पैसा नहीं था और राज्यों को जरूरत थी, इसलिए Rs. 1.1 lakh crore in the year 2020-21 and Rs. 1.59 lakh core in the year 2021-22 ; यानि 2.69 लाख करोड़ रूपए बैंक टू बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लेकर राज्यों को राहत पहुँचाने का काम किया है। यह लोन with interest वापस करना पड़ेगा। यह जो 2.69 लाख करोड़ रूपए का लोन है, इसका interest 54,000 करोड़ रूपए होता है, यानि हमें कुल 3.23 लाख करोड़ रूपया repay करना है। इसके अलावा 2020-21 और 2021-22 के जो arrears है, that is, about Rs. 3.16 lakh crore, चूँकि हमने 14 परसेंट ग्रोथ assure की थी, लेकिन कोविड में सरकार ने कहा कि 14 परसेंट ग्रोथ देना संभव नहीं है, इसलिए हम केवल 7 परसेंट ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे यानी कुल मिला कर Rs. 6,39,000 crore, which includes Rs. 3.23 lakh crore as the interest plus the principal repayment, जो Compensation arrears हैं, उसको repay करना है। महोदय, compensation period को बढ़ाया गया है, उसमें जो भी राशि प्राप्त होगी, वह राशि 6.39 लाख करोड़ रूपए को repay करने में ही खर्च हो जाएगी।

Rate rationalization के लिए कमेटी बनी हुई है, लेकिन कोविड के कारण crisis की स्थिति है, उसमें टैक्स को रिवाइज नहीं किया जा सकता। कोई टैक्स बढ़ा नहीं सकते हैं। यह समय टैक्स बढ़ाने का उपयुक्त समय नहीं है, इसलिए जीएसटी काउंसिल को इस बात को विचार करना होगा और यह जिम्मेवारी केवल केन्द्र सरकार की नहीं है और जैसा कि मैंने कहा कि केन्द्र ने यह आश्वासन नहीं दिया था कि हम आपकों अपने खजाने से 14 परसेंट की ग्रोथ compensate करेंगे। यह जो सेस की आमदानी

होगी, उसके द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जानी थी। अब जीएसटी काउंसिल को यह निर्णय लेना है कि आगे आने वाले दिनों में राज्यों को होने वाली एक लाख करोड़ रूपए से ज्यादा की जो क्षति है, उसकी पूर्ति कैसे होगी।

महोदय, मैं निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि क्रिप्टों के बारे में जितने भ्रम थे, उन्होंने सारे भ्रमों को दूर करने का काम किया है। उन्होनें 30 percent income from transfer of crypto assets plus cesss and surcharge लगाया है। Mining is not part of acquisition cost, 1% TDS is for tracking the transaction. Crypto और NFT के बारे जो advertisements हैं,उनमें भी risk disclaimer देना पड़ेगा।

महोदय, यह क्रिप्टों आखिर क्या है। It is neither a commodity, nor an asset; it is not a good; it is not a service. आखिर यह क्या है? इसकी कोई intrinsic value नहीं है, इसके पीछे किसी कंपनी की ताकत नहीं है। मैं तो निर्मला जी से आग्रह करूँगा कि आपने इस पर 30 परसेंट का टैक्स लगाया है, इसे आगे आने वाले दिनों में बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। महोदय, यह क्रिप्टों gambiling है, जुआ है। यह एक प्रकार की lottery है, एक प्रकार की horse racing है, अगर आप किसी शेयर में पैसा लगाते हें, तो आपको मालूम है कि टाटा या कोई और कंपनी उसके पीछे है, लेकिन क्रिप्टों के पीछे कौन है? इस पर जापान ने 55 परसेंट, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया ने upto 45 per cent, यूएस ने 37 परसेंट तक टैक्स लगाया है, इसलिए मैं निर्मला जी से आग्रह करूँगा कि आप इस पर विचारा कीजिए कि क्या हम आगें आने वाले दिनों में क्रिप्टों पर 30% परसेंट से ज्यादा टैक्स लगाने का विचार कर सकते हैं?

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : महोदय, क्रिप्टो से पैसा कमाने वाले लोगों को 30% से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि क्रिप्टों करेंसीज का जो CAGR (Compounded Average Growth Rate) है, वह बिटकॉइन का 115% है, Ethereum का 30% है, Binance Coin का 151% है। So, investors are attracted by exteraordinay profits. महोदय, Swaminathan Ankleswar Aiyar ने अपने एक आर्टिकल में लिखा – Cryptocurrency has no underlying value not even a tulip of 17th Century speculative bubbles. 17वीं शताब्दी

में यूरोप के एक देश के अंदर Tulip के फूल के लिए होड़ मच गई, हर आदमी Tulip खरीद रहा था उसका दाम 200 गुना हो गया, लेकिन एक दिन अचानक जब bubbles brust हुआ, तब हजारों लोग कंगाल हो गए। Tulip की कीमत कम से कम एक रूपया तो होगी, लेकिन क्रिप्टों की कीमत क्या है, यह कोई नहीं जानता है।

महोदय, यूक्रेन ने सात दिन पहले क्रिप्टोंकरेंसी को legalize कर दिया। Dubai में Dubai Virtual Asset Regulatory Authority का गठन किया गया है। ब्रिटेन ने भी Crypto स्टडी करने का निर्णय लिया है। क्रिप्टों करेंसी में बड़े पैमाने पर फ्रॉड हो रहा है। एक स्टडी के अनुसार, criminals made a record 14 billion dollars in 2021. केरल के अंदर Abdul Gafoor नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया है, जो क्रिप्टोकरेंसी के फेक रैकेट में शामिल था। इस 1,200 करोड़ के रैकेट में कई लोग पकड़े गए है। अब एक अप्रैल से पहले-पहले investors started parking these currencies in private wallets. 8 billion dollar worth crypto assets is expected to go out of country.

महोदय, मैं ऑनलाइन गेमिंग के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर gambling हो रही है। मैं गेमिंग के विरोध में नही हूँ। एक अनुमान है कि 2022 के अंदर केवल fantasy game की 2.8 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होगी। केवल ऑनलाइन गेमिंग, हीं नहीं Online Landing को भी कैसे regulate किया जाए? आज का समाचार है कि करीब 40 से ज्यादा Digital lending applications found to be run by Chinese nationals. ऑनलाइन लेंडिंग, सोशल मीडिया, EdTech, ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, इन्हें कैसे regulate किया जाए? यह जो आईटी कानून बना हुआ है, यह 20 साल पुराना है। मैं सरकार से आग्रह करूँगा की आईटी एक्ट को नए सिरे से ड्राफ्ट किया जाए, ताकि वह वर्तमान की चुनौतियों का मुकाबला कर सके।

इसके साथ ही, मैं निर्मला जी से भी आग्रह करूँगा कि IMF, World Bank, Financial Stability Board के साथ मिलकर device a framework, बहुत जल्द एक पेपर पब्लिश किया जाए, ताकि Public Consultation प्रारम्भ हो सके कि क्रिप्टो क्या है? NFT क्या है? क्या किया

जाना चाहिए। वर्चुअल डिजिटल करेंसी की जो घोषणा की गई है, उस पर भी जल्द से जल्द विचार किया जाए।

महोदय, क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री पर केवल 18% जीएसटी लगता है, वह भी जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो exchange चलाने वाले लोग हैं, वे जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस पर 18% टैक्स लगता है। मैंने इसे Zero Hour में भी उठाया था, because it is no asset, nor security, nor commodity, nor goods, nor service and cryptos are similar to lottery, casinos, betting, gambling, horse racing और इन सारी चीजों की पूरी transaction value पर 28% टैक्स लगता है। अगर आप लॉटरी में 100 रूपये लगाएं, तो आपको 28 रूपये टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप Casino में 1,000 रूपये की Bet लगाएँ, तो आपको 28% टैक्स देना पड़ेगा और गोल्ड पर भी 3% जीएसटी पूरे transaction पर देना पड़ेगा। इसलिए भले ही वह 0.1% हो, लेकिन क्रिप्टो की जो total transaction value है, उस पर जीएसटी लगाने के बारे में विचार करना चाहिए।

महोदय, इस सदन में बैंकों पर काफी चर्चा होती रही है। के.वी. कामथ, जो इंडियन बैंकिंग के गुरू माने जाते हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक लेख में लिखा – In more than 50 years, I have been in banking business. I have never seen their balance sheets as clean and healthy as today in terms of bad assets. हमने 50 सालों में आज तक बैंकों की इतनी बेहतर व्यवस्था को नहीं देखा है।

SHRI SUSHIL KUMAR MODI (CONTD) : India's banking industry is in its best shape in terms of quality of assets and quantum of capital. Indian Rating and Research रेटिंग एजेंसी का मत है – Banking system health is at best in decades.

महोदय, 2014 में बैकों का NPA 2.16 लाख करोड़ था जो 2018 में 5 गुणा बढ़कर 10.36 लाख करोड़ हो गया। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि अगर एनपीए बढ़ा, तो वह इसलिए बढ़ा, क्योंकि UPA के 10 साल के कार्यकाल के अंदर aggressive lending किया गया। लोगों को टेलिफोन पर बैंकों से पैसा दिया जाता था, पैरवी के आधार पर दिया जाता था, इसलिए वर्ष 2008 में जहाँ 25 लाख करोड़ बैंकों की lending थी, वह छः साल में बढ़कर 68 लाख करोड़ हो गई।

नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनते ही asset quality review हेतू एक कमिटी बनाई गई। रिव्यू किया गया और एनपीए के कारणों का आइडेंटिफाई करना प्रारम्भ किया। कानून में प्रावधानों को कठोर किया गया। SARFAESI Act. में तीन महीनें की जेल का प्रावधान किया गया। अगर कोई willful defaulter है, तो debarred from floating new venture for five years. यदि वह कंपनी में डायरेक्टर है, तो कैपिटल मार्केट में कोई नया इश्यू रेज़ नहीं कर सकता है। महोदय, इन सारी चीजों का परिणाम हुआ कि 31 मार्च, 2018 को जहाँ एनपीए 11.18 परसेंट था, वह एनपीए वर्ष 2021 में घटकर 6.39% हो गया। यह है नरेन्द्र मोदी की सरकार, जिनके कार्यकाल में बैंकों की हालत बेहतर हुई है।

महोदय, बैंकों को कैपिटल की आवश्यकता थी। जब बैंकों की हालत खराब होने लगी तो सरकार ने बैंकों को कैपिटल देने शुरू किया। This Government has provided 3.60 लाख करोड़ to the banks as capital infusion. वर्ष 2018 में एनपीए के कारण बैंकों की हालात खराब थी, तब 90,000 करोड़ infuse किया गया, वर्ष 2019 में 1,06,000 करोड़ infuse किया गया। In the year 2021-22, बजट में प्रोवाइड किया गया कि कैपिटल के रूप में 15,000 करोड. infuse करेंगे लेकिन केवल 46,00 करोड़ की आवश्यकता पड़ी और 10,000 करोड़ की बचत हो गई। वर्ष 2023-24 के बजट में कोई प्रोविजन नहीं किया गया है, क्योंकि बैंकों में सरकार को कैपिटल Infuse करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

महोदय, आज बैंकों की स्थिति बेहतर हुई है, उनकी आमदनी बढ़ गई है। एसबीआई को जहाँ वर्ष 2016-17 में 1,300 करोड़ का लॉस था, वहीं वर्ष 2021 में 20,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा का जहाँ वर्ष 2018-19 में Rs. 8,000 Crores का लॉस था, वहीं अब Rs. 828 crores का प्रॉफिट है। Punjab National Bank को जहाँ वर्ष 2019-20 में 8,000 करोड़ का लॉस था, वहीं वर्ष 2020-21 में उसे Rs. 2,000 crore का प्रॉफिट है।

महोदय, Congress के लोग corruption के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं। चुनाव में कहा जाता था कि नीरव मोदी, नरेन्द्र मोदी, आपने भगा

दिया।... (व्यवधान).. उपसभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि विजय माल्या , नीरव मोदी और मेहल चौकसी , जिन्होंने Rs. 22,585 करोड़ का fraud करके public sector banks के पैसे को siphon किया था, divert किया था, out of that Rs. 22,585 crores, Rs. 19,111 crores की प्रॉपर्टी attach की जा चुकी है। Rs. 15,113 crores की संपति बैंकों को वापस सौंप दी गई है। इतना नही नहीं, बैंकों को जो 15,113 करोड़ की संपति वापस मिली, उसको बेचकर बैंकों ने 8,000 करोड़ की राशि प्राप्त कर ली है। महोदय, नरेन्द्र मोदी से कोई बचकर नही जा पाएगा, चाहे वह विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो या मेहुल चौकसी हो।

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : महोदय, हमने तो कार्रवाई कर दी, लेकिन आपकी क्या स्थिति है? इसी सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि 6 राज्यों के अंदर 128 Bank froud के Case pending हैं। सीबीआई ने मांग की कि हमें consent दीजिए, permission दीजिए, क्योंकि आपने general consent withdraw कर लिया। डेढ़ साल का समय हो गया, आपने consent देने से इंकार कर दिया। महोदय, डेढ़ साल से 21,000 करोड़ के 128 cases pending हैं, लेकिन राज्य सरकार consent नहीं दे रही है। यहां प्रफुल्ल पटेल जी बैठे हैं, आप अपने मुख्य मंत्री जी से बात कीजिए। सबसे ज्यादा 101 मामले, जिसमें 20,312 करोड़ के cases महाराष्ट्र में pending हैं। पंजाब में 298 करोड के और बंगाल में 293 करोड़ के 6 cases pending हैं। एक का भी consent नहीं दिया गया। आप कहते हैं कि हमने विजय माल्या पर कार्रवाई नहीं की, हमने कार्रवाई कर दी, लेकिन जो पब्लिक सेंटर बैंक्स के fraud हैं, इसमें consent की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। जिन राज्यों ने consent withdraw कर लिया, वहाँ पूछने की आवश्यकता पड़ रही है।

महोदय, महाराष्ट्र में मनोज जायसवाल, अभिजीत जायसवाल, अभिषेक और मुन्ना राजीव जायसवाल कौन हैं? डेढ़ साल से Corporate Power Limited. जिनका 4,000 करोड़ रूपये का bank fraud था, उसमें आपने परमिशन नहीं दी। येस बैंक के सीएमडी राणा कपूर, जिसका 15,000 करोड़ का consent डेढ़ साल से Pending है, आपने consent क्यों नहीं दिया? महोदय,

ABG shipyard के मामले में आपने 14 महीने तक consent नहीं दिया, जबकि banks ने 14 माह पहले ही complain file कर दिया था।

महोदय, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, आजादी के बाद के उसके सारे रिकॉड टूट गए और 10 दिन पहले ही 400 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट टारगेट पूरा कर लिया गया।

महोदय, प्रधान मंत्री जी ने कहा कि Local goes Global, History has been scripted, Milestone in India's journey towards Aatmanirbhar Bharat. महोदय, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हम 23 बिलियन का टारगेट पार करने जा रहे हैं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का एक्सपोर्टर है, हम 90 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। महोदय, हम गेहूँ का एक्सपोर्ट 380 परसेंट ज्यादा कर रहे हैं। यूक्रेन-रूस crisis के कारण पूरी दुनिया के अंदर गेहूं का संकट पैदा हुआ है, लेकिन आज मध्य प्रदेश, पंजाब और बाकी राज्यों में किसानों को बाजार में एमएसपी से 200 रूपये ज्यादा मिल रहा है।

महोदय, मोबाइल Apple ने 12 हजार करोड़ रूपये के मोबाईल फोन एक्सपोर्ट किया है और सैमसंग ने भी 12 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। वर्ष 201718 में जहां 1,300 करोड़ रूपये के स्मार्ट फोन एक्सपोर्ट किए गए थे, वह 32 times बढ़ गया और वर्ष 2021-22 में 42 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा के स्मार्ट फोन भारत से एक्सपोर्ट किया गया है। जबकि Semiconductors की कमी थी, lockdown के कारण disruption था, चीन से तनाव के कारण components के आने में देर हो रही थी, लेकिन यह PLI scheme का कमाल है कि अब एप्पल और सैमसंग ने भी अपने सेंटर्स यहां स्थापित कर लिए हैं।

महोदय, One rank, One pension Scheme को सुप्रीम कोर्ट में challenge किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा "No constitutional infirmity." जिस तरह से OROP भारत सरकार ने लागू किया है, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। महोदय, पूरे डिफेंस बजट का 1/5वां हिस्सा केवल पेंशन में जाता है। वर्ष 2013-14 में 45 हजार करोड़ रूपये की pension liability थी, वह बढ़कर अब 1 लाख, 28 हजार करोड़ हो गई है। वह लगभग 4 गुना बढ़ गई, लेकिन 36 लाख से ज्यादा सैनिक और

सिविल डिफेंस के लोगों के लिए OROP लागू करके नरेन्द्र मोदी जी ने वायदे को पूरा करने का काम किया है।

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : यहां बार-बार inflation की चर्चा हो रही है। शक्तिसिंह गोहिल जी ने तो inflation पर ही दो-तिहाई समय लगा दिया। अमेरिका को 40 साल बाद महंगाई face करनी पड़ रही है। अमेरिका में 7.9% inflation है which is 40 years high, यू.के. के अंदर 30 साल में सबसे ज्यादा महंगाई 6.2 per cent है। Euro Zone, जिसमें 27 देश यूरो का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर 5.8 per cent inflation rate है और भारत में inflation rate 6.07 per cent है।

(उपसभाध्यक्ष, श्री भुबनेश्वर कालिता पीठासीन हुए) : महोदय, 2022 में inflation rate 6 के आस-पास है, वर्ष 2008 में आपकी सरकार थी, तब inflation rate 8.4 per cent था; 2009 में 10.9 per cent; 2010 में 12 per cent inflation rate था, 2012 में 9.3 per cent; 2013 में 11.1 per cent था। Congress के राज में double digit inflation rate था। आज नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने Inflation को RBI द्वारा निर्धारित 6% (+ -2) के within रोक कर रखा है। इससे कौन इन्कार करेगा कि दाम नही बढ़े है। अगर यूक्रेन-रूस का युद्ध नहीं होता, तो आज पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ता,....(व्यवधान)... हमने महंगाई पर नियंत्रण कर लिया होता।

महोदय, यूक्रेन की लड़ाई, कोविड, भारत-चीन सीमा पर तनाव के बावजूद 2021-22 का ग्रोथ रेट का आंकड़ा, Fitch Rating के अनुसार 8.70, World Bank-8.30, IMF-9 per cent है। वर्ष 2021-22 में भारत दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट वाले देशों में से एक होगा। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये Fitch, World Bank, Moody's, IMF and RBI के आंकड़े हैं। इन सारी विपरीत परिस्थितियों में न जुलूस निकला, न प्रदर्शन हुआ और न ही कहीं लॉकडाउन का विरोध हुआ।

श्री नरेन्द्र मोदी जी की लोकप्रियता लागातार बढ़ती जा रही है और दूसरे देशों में वहां के प्रधानमंत्रियों की लोकप्रियता घटती जा रही है। Morning Consult नाम की site है, जो survey करती है, उसने यह पाया कि श्री नरेन्द्र मोदी 77% rating के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजनेता हैं। Biden Rating 41% है, वे सातवें नंबर पर हैं और Mexican

Prime Minister नंबर दो पर है। मैं केवल यह बता रहा हूँ कि यह कोई सामान्य काम नहीं था, जिस प्रकार से हमने कोविड का मुकाबला किया, जिस प्रकार से हमने इन विपरीत परिस्थितियों में काम किया है।

महोदय, मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि अगर नरेन्द्र मोदी जी नहीं होते, तो इन चुनौतियों का मुकाबला नहीं हो पाता। ये नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार थी, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। यह व्यक्ति टकाराना जानता है, जिसको take the bull by the horns कहते हैं। वह डरता नहीं है, घबराता नहीं है, वह हर चुनौती को अवसर में बदलता है और सफलता उनके कदमों को चूमती है।

अंत में, मैं इतना ही कहूँगा कि सीढ़िया उन्हें मुबारक हों, जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। जिनको केवल छत तक जाना है, वे सीढ़ी पर चढ़कर चले जाएं।

''सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो,
जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है।
मेरी मंजिल तो आसमां है,
रास्ता खुद मुझे बनाना है।''

महोदय, मैं इन्ही शब्दों के साथ निर्मला जी को और आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

The Chartered Accountants, The Cost & Works Accountants and The Company Secretaries Bill, 2021

पर

भाषण

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : माननीय उप सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, पिछले पाँच वर्षों में पाँच लाख से ज्यादा कंपनियों के नाम कंपनी रजिस्ट्रार के रजिस्टर से हटाने पड़े। महोदय, 2007 से 2009 के दौरान 3 लाख, 79 हजार कंपनियों के नाम हटाने पड़े और यह पाया गया कि ज्यादातर कंपनियाँ बैंक फ्रांड, चीटिंग एवं अन्य गैर-कानूनी कार्यों में शामिल हैं। इन पांच लाख कंपनियों में से करीब 2.38 लाख कंपनियाँ shell companies थी। एक ही एड्रेस पर 100-100 कंपनियाँ थी। बड़ी संख्या में ऐसी कंपनियाँ थी, जिनका न तो कोई पता-ठिकाना था और न ही इनका कोई कार्यालय था। इन सारी shell companies के पीछे कहीं न कहीं किसी CA का दिमाग था और वे उसमें शामिल थे।

समाचार पत्रों में सुर्खियाँ थी ED arrests a CA in Hyderabad for aiding shell companies launder funds to Hong Kong, ED arrests a Delhi CA in money-laundring case leads to fertilizer scam, 8 CAs arrested for GST fraud, 16 arrested for gambling, 3 CAs arrested, CGST official and 2 CAs arrested on charge of extortion. महोदय, पिछले पाँच सालों में पाया गया कि Chartered Accountants में कुछ लोग shell companies बनाकर भ्रष्टाचार को प्रश्रय दे रहे हैं, इसलिए सरकार को मजबूरन इस बिल को लाना पड़ा।

जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि हम उनकी परीक्षा पद्धति में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। उनके examination में, उनके curriculum में, उनके result में, उनके license और अन्य सारी चीजों में उन्हें स्वायत्तता है, किन्तु केवल एक जगह जहाँ पर सरकार हस्तक्षेप नहीं, वरन् उसे मजबूत करना चाहती है वह Disciplinary Committee है। महोदय, अभी वहाँ चार Disciplinary Committees हैं, जिनमें से तीन के चेयरमैन कौन

हैं-तो ICAI के President हैं, वही तीनों कमेटियों के चेयरमैन हैं। इसी प्रकार चौथे जोन के Disciplinary Committees के चेयरमैन कौन हैं- तो Vice President चौथे जोन के Disciplinary Committees के चेयरमैन हैं।

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत): महोदय, यहाँ conflict of interest है, जो चेयरमैन होता है, करोड़ों रूपये खर्च कर चेयरमैन बनता है, इसलिए वह अपने मेम्बर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है। पिछले वर्षों में पाया गया कि सैकड़ों की संख्या में केसेज पेंडिंग हैं, वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको दबाकर रखा गया, flimsy ground पर उनको रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ तक की सीबीआई, ईडी और सरकार ने जो complaint recommend की थी, उस पर भी वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

महोदय, जहाँ तक Disciplinary कमेटी के Composition की बात है, उसमें प्रावधान है कि Presiding Officer नॉन-सीए होगा। यह कहा जाता है कि उसे expertise नहीं है लेकिन Disciplinary Committee का जो निर्णय अपील में ट्रिब्यूनल में जाता है, वहाँ तो कोई सीए नहीं है। ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, वहाँ तो कोई सीए नहीं है। हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, वहाँ तो कोई सीए नहीं है। साथ ही, Director Discipline CA होता है। Directorate में 22 में से 11 CA होते है जो पूरा केस तैयार करते हैं। अतः Presiding Officer non CA के रहने से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो conflict of interest था, केवल उसी को दूर करने का प्रयास किया गया है और केवल यह कहा गया है कि Disciplinary Committee का Presiding Officer नॉन-सीए होगा।

महोदय, इसके मेम्बर्स को पहले सरकार नॉमिनेट करती थी, लेकिन अब सरकार उनको नॉमिनेट नहीं करेगी, बल्कि सीए की जो काउंसिल है, वह एक पैनल तैयार करेगी और उसी पैनल में से सरकार नामों का चयन करेगी। इस तरह से केन्द्र सरकार को सदस्यों को नॉमिनेट करने का जो अधिकार था, वह भी समाप्त हो गया। आप Presiding Officers का पैनल

बनाइए, सरकार उसमें से चयन करेगी। आप मेम्बर्स का पैनल बनाइए, सरकार उसमें से चयन करेगी। फिर lay members का experience in the field of law, economics, business, finance, accountancy की बात कही गई है।

महोदय, तीसरी बात यह है कि 2,500 करोड़ रूपये से ज्यादा का फंड आईसीएआई का है। इसमें केवल यह प्रावधान है कि सीएजी के ऑडिटर्स पैनल में से नाम तय कीजिए और आप जो नाम तय करेंगे, वहीं ऑडिट करेगा, सरकार या सीएजी ऑडिट नहीं करेगी। महोदय, पिछले दिनों फण्ड के दुरूपयोग के कई मामले आए हैं। एक समय में आईडीबीआई का टियर-II का जो bond था, उसमें करीब 800 करोड़ रूपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, जो regulation के खिलाफ था। बैंकों में पैसा जमा करने के लिए होड़ मची रहती है और लोगों को मालूम है कि अगर किसी बैंक में पैसा जमा करेंगे, तो उसके बदले में क्या मिलता है।

महोदय, Disciplinary Committee को, केवल strengthen करने का काम किया गया है। दुनिया के अधिकांश देशों में, चाहे यूएसए हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या साउथ अफ्रीका हो, सभी देशों के अंदर जो अकाउंटिंग संस्थाएँ हैं, उनकी जो Disciplinary Committee है, उसमें नॉन-सीए ही मेम्बर्स होते हैं ताकि conflict of interest न रहे, separation of elected bodies' members from investigation and disciplinary process है।

भारत में एक केवल एक आईसीएआई है, जो सीए की डिग्री प्रदान करता है। अमेरिका में 56 Boards हैं और उन boards के appointments सरकार करती है। साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक की International Federation of Accountants जिसमें 130 देशों के 175 लोग मेम्बर हैं उसकी अनुशंसा है कि Disciplinary Committee के अंदर non-accounting के लोग ही मेम्बर होने चाहिए ताकि वे दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें। अगर इसमें conflict of interest होगा, तो वे ऐसा नहीं कर पाएँगे।

महोदय, कहा जा रहा है कि Co-ordination Committee की क्या आवश्यकता है। इन लोगों ने सन् 2000 में एक एमओयू साइन किया जिसमें यह प्रावधान था कि तीनों संगठन आपस में coordination करेंगे, लेकिन 16 साल हो गए, एक बैठक नहीं हुई, बैठक का एजेंडा पता नही। अब सरकार ने कहा कि जो तीनों संस्थाएँ हैं, उकने लिए Coordination Committee होगी...

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : जिसको कम्पनी अफेयर्स के सेक्रेटरी preside करेंगे। तीनों संस्थाओं के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी उसके मेम्बर्स होगें। महोदय, इसमें क्या आपत्ति है! इसका भी विरोध किया जा रहा है।

महोदय, अभी तक सिर्फ Chartered Accountants पर कार्रवाई करने का अधिकार था, लेकिन जो Chartered Accountant Firms हैं, उन पर Chartered Accountant Insititutes को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था। यह सदन Satyam Scandal के बारे में जानता है कि 7100 करोड़ रूपये से ज्यादा का आईटी का फ्रॉड हुआ था, उसके बाद आईसीएआई ने स्वयं रिकमंड किया कि जो Chartered Accountant की Firms हैं, उन पर भी कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाए। महोदय, इस बिल के द्वारा केवल मेम्बर्स ही नहीं – कोई मेम्बर जो किसी फर्म का सदस्य है, अगर उसके खिलाफ लगातार पाँच साल तक शिकायत मिल रही है तो उस स्थिति में अधिकतम 25 लाख रूपये तक उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसके मेम्बर को या firm को debar किया जा सकता है।

महोदय, पहले कोई timeline नहीं था कि कितने दिनों में proceeding पूरी होगी, अब इसमें प्रावधान किया गया है कि 365 दिनों के अंदर proceeding पूरी हो जाएगी। पहले यह प्रावधान था कि कोई भी शिकायतकर्ता withdraw कर सकता है। आपने complaint file की और आप मिल गए, कुछ under-hand deal हो गई, फिर वह complaint withdraw कर ली गई, लेकिन अब इसमें यह प्रावधान किया गया है कि 'withdrawal complaint not permissible.' इसमें कोई complaint को withdraw नहीं कर सकता।

महोदय, पहले जो चेयरमैन था, उसी के पास सेक्रेटरी का भी पावर था।

सारे पावर्स चेयरमैन के पास था। अब प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की पावर्स में विभाजन किया गया है, उनकी पावर्स को अलग-अलग किया गया है।

महोदय, NFRA (National Financial Reporting Authority) बनी है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो listed companies हैं, जो unlisted companies हैं, जिनका turnover पाँच सौ करोड़ रूपये से ज्यादा का है, जो बैंक्स हैं, जो insurance companies हैं उनके accounting standards को NFRA निर्धारित करेगी। यानि इनको CA संस्थानों के दायरे से बाहर कर दिया गया है। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का एलान किया है, उसको पूर्णता तक पहुँचाने के लिए यह आवश्यक था कि Chartered Accountants की जो Disciplinary Committee है, इसको और अधिक strengthen किया जाए।

महोदय, ऐसा नहीं है कि सारे CA गलत हैं। मैं कुछ समय पहले एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल में अबू धाबी गया था। जहाँ 800 से ज्यादा Chartered Accountants हैं। केवल दुबई में 1,500 से ज्यादा Chartered Accountants हैं। हमारे Chartered Accountants ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रौशन किया है। जब कोई कहता है कि मैं CA हूँ, तो समाज में IAS, IPS के समान उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। अधिकांश Chartered Accountants ईमानदारी से काम करते हैं। प्रधान मंत्री जी ने ICAI के सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा कि आप client के लिए काम मत कीजिए,आप देश के लिए काम कीजिए। Client के लिए काम करना अलग बात है और देश के लिए काम करना एक अलग बात है।

उप सभापति महोदय, मैं निर्मला सीतारमण जी को और आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी प्रेरणा से यह बिल इस सदन के अंदर आया है और मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, किसी की autonomy प्रभावित नहीं होगी। केवल गलत लोगों पर कार्रवाई करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं, धन्यवाद ।

श्री उप सभापित : सुशील कुमार मोदी जी, धन्यवाद। अब माननीय मंत्री महोदय का रिप्लाई होगा।

केन्द्रीय विद्यालय में सांसद कोटा
समाप्त करने
सम्बन्धी प्रश्न

श्री सुशील कुमार मोदी : महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह आग्रह करूँगा कि there is a 17-seat quota, that is, sponsoring authority quota in each and every Kendriya Vidyalaya, which is being used by the District Collector. यह 17 का कोटा प्रत्येक विद्यालय में है, 5 in class 1 के हरेक section में, कक्षा 2 से 8 में 10 का कोटा और 2 discretionary quota है। That comes about 22,000 जिसमें न तो कोई Merit है और न ही कोई reservation है। क्या सरकार 22,000 sponsoring authority quota समाप्त करने का विचार रखती है?

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान सदस्य, आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी ने जो चिन्ता जाहिर की है, निश्चित रूप से समय-समय पर केन्द्रीय विद्यालयों में नामांकन से सम्बन्धित यह चर्चा राज्य सभा में भी और लोक सभा में भी उठती रही है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों लोक सभा में भी इस पर चर्चा हुई है।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी (क्रमागत) : आदरणीय अध्यक्ष जी ने चेयर से नियमन दिया है कि सभी दलों के नेताओं के साथ इस पर विस्तृत चर्चा होगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। मैं आज इस सदन के माध्यम से माननीय सदस्य जी से कहना चाहती हूँ कि ये लगभग सभी की चिंता है इसलिए विभाग ने यह तय किया है कि आप सभी के साथ चर्चा करने के बाद जैसा आप सभी का निर्णय होगा, उस पर विभाग गंभीरता से विचार करेगा।

श्री सुशील कुमार मोदी : महोदय, मैंने sponsoring authority quota का जिक्र किया था। This is not M.P. quota. This is sponsoring authority quota, which is different from M.P. quota. Now, I come to my second supplementary. महोदय, मैं सबसे पहले शिक्षा मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना Ministerial

quota समाप्त कर दिया है। मैं माननीया मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहूँगा कि M.P. quota को बढ़ाया जाना संभव नहीं है और यदि बढ़ा भी देंगे, तो भी लोगों की नाराजगी बनी ही रहेगी। क्या सरकार ने जिस प्रकार से मंत्री कोटा समाप्त कर दिया है, उसी प्रकार से M.P. quota को समाप्त करने का विचार रखती है?

उपसभाध्यक्ष (डॉ. सस्मित पात्रा) : माननीय मंत्री जी, प्लीज...(व्यवधान)... माननीय थंबीदुरई जी, प्लीज। Hon'. Minister, please start. ...(Interruptions)....

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : माननीय उप सभाध्यक्ष महोदय, जैसा आदरणीय सदस्य ने कहा, चाहे किसी भी तरह का कोटा हो, मैंने पहले भी कहा कि इस पर लगातार चर्चा हो रही है। क्योंकि इसमें आरक्षण नीति का पालन नहीं हो रहा है या अन्य विसंगतियाँ हैं। मैं फिर से यह कहना चाहूँगी कि सभी का जो भी निर्णय होगा, उस पर विभाग गंभीरता पूर्वक विचार करेगा।

उप सभाध्यक्ष (डॉ. सस्मित पात्रा) : माननीय श्री संजय सिंह जी।

श्री संजय सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय सदस्य श्री सुशील कुमार मोदी जी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है। सर, मेरा Microphone नहीं चल रहा है।

उप सभाध्यक्ष (डॉ. सस्मित पात्रा) : Microphone नहीं चल रहा है, कृपया आप स्विच ऑन कर लीजिए। देखिए, चालू हो गया।

श्री संजय सिंह : महोदय, मैं ज्यादा तेज बोलता हूँ, तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम होती है और माइक चालू कराता हूँ, तब भी प्रॉब्लम होती है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि केन्द्रीय विद्यालयों के प्रति लोगों में एक भरोसा और आकर्षण है। मैं सबसे पहले इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। महोदय, देश के सभी लोग यह चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और केन्द्रीय विद्यालयों में अच्छी शिक्षा मिलती है, इस कारण चाहे गरीब आदमी हो या आम आदमी हो, वह यह चाहता है कि उसके बच्चे का केन्द्रीय विद्यालय में दाखिला हो जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार देश में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है? यदि आप इनकी संख्या

बढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो सांसदों का कोटा है, उसे भी बढ़ाइये अन्यथा 10 के कोटे में हम लोगों को सिर्फ नाराज़गी के अलावा और कुछ नहीं मिलता है।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : उप सभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने केन्द्रीय विद्यालय खोलने के बारे में कहा है। इस संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि केन्द्रीय विद्यालय खोलने के संबंध में राज्य से प्रस्ताव आते हैं इसके लिए एक पद्धति है, उसके माध्यम से प्रस्ताव कमेटी में जाता है और कमेटी उस पर विचार करती है। उसके बाद हम केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय करते हैं।

जहाँ तक कोटा बढ़ाने या समाप्त करने की बात है, इस संबंध में पहले भी बात हुई है, इसलिए हम फिर से यही कहेंगे कि सरकार और विभाग इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं।

श्री विवेक ठाकुर : उप सभाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से केन्द्रीय विद्यालय के कोटे के संबंध में तरह-तरह के मत चल रहे हैं। यह बात स्पष्ट है कि सभी सांसद इस 10 के चक्कर में दबाव में हैं।

उप सभाध्यक्ष (डॉ. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्य, कृपया आप अपना सवाल पूछें।

श्री विवेक ठाकुर : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि New Education Policy की भी बात हो रही है। 130 करोड़ की आबादी में 14,35,562 बच्चे केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ते हैं और 44,816 कर्मचारी हैं। अगर आप अनुपात देखें, तो 32 छात्रों पर एक कर्मचारी होता है। Pupil-teacher ratio की भी बात हो रही है, लेकिन हम abruptly end करके वह टारगेट achieve नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर कोई जी.डी. गोयनका या दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले माँ-बाप नहीं आते हैं।

उप सभाध्यक्ष (डॉ. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्य, कृपया आप अपना सवाल पूछें।

श्री विवेक ठाकुर : उप सभाध्यक्ष महोदय, मैं दो उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ पेड़ के नीचे दाढ़ी बनाने वाला जो है, मैं उसकी जाति भी नहीं पूछ सकता हूँ, वह गरीब है, इतना जानता हूँ कि उसकी बच्ची पढ़ी और बेंगलुरू गई।

उप सभाध्यक्ष (डॉ. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्य, आपका सवाल क्या है?

श्री विवेक ठाकुर : उप सभाअध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि डीएम और कमिश्नर के जो discretionary quota हैं, क्या उनको divert करके public representatives के quota को बढ़ाया जा सकता है? दूसरी बात यह है**.....**(व्यवधान)**....**

श्री विवेक ठाकुर : उप सभाध्यक्ष महोदय, लास्ट इयर मिनिस्ट्री का कोटा nil हुआ, suspend हुआ, वह abolish हुआ या नहीं हुआ, यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। उसके पहले 12,295 admissions हुए।

The Vice-chairman (Dr. Sasmit Ptra) : I will have to move on. इतना लंबा सवाल नहीं ले सकते । Please ask only one question.

Shri Vivek Thakur : No, Sir. What i am saying is that if you divide it amongst all the Members of parliament of Lok Sabha and Rajya Sabha, still it is an enhancement of 15, and, that is the need of the hour.

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : उप सभाध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार शिक्षा के सार्वभौमिक पहुँच के साथ-साथ सभी के लिए समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं माननीय सदस्य से फिर से यह कहना चाहूँगी कि जिस कोटा की चिंता सभी माननीय सदस्य कर रहे हैं, विभाग सभी तरह के कोटे पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है। अभी सभी सम्मानित विद्वान, सभी माननीय सदस्यों ने तथा लोक सभा के माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उन्होंने भी कहा है, हम सभी की राय लेंगे और उन पर विचार-विमर्श करने के उपरान्त विभाग इस पर निर्णय लेगा।**....** (Interruptions)**...**

A Quota Too Many

(इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 24 मार्च, 2022 को प्रकाशित मेरा लेख)

There are few issues on which the legislative and judicial stances have wavered with such frequency over the years as the Special Dispensation Scheme for admissions in Kendriya Vidyalayas. Introduced in 1975, this measure has been in continuous flux with shifting standpoints between the KV's Board of Governors, its Joint Action Committees, the Law Ministry and the Ministry of Human Resource Development. The scheme has been abolished thrice since its inception but after every withdrawal, it was subsequently reintroduced. That a discretionary provision has witnessed so many inflections with the latest amendment as recently in 2016-17, bespeaks the inherently flawed nature of this scheme.

Currently, the scheme allows every Member of Parliament to recommend 10 students every academic year to Kendriya Vidyalayas for availing of exclusive admissions. Initially, MPs could refer only 2 cases for admissions when the scheme was reintroduced in 1998 after its first withdrawal in 1997. Over the years, after going through two more abolishments including a High Court strike down, and a second restoration in 2010, the quota was increased from 2 cases to 5 cases per MP in May of 2011. Subsequently, the quota was further enhanced twice: from 5 to 6 in 2012 and then from 6 to the currently existing 10 seats per MP in 2016.

Considering there are 543 MPs in Lok Sabha and 245 MPs in Rajya Sabha, a total of 7880 admissions are executed through this quota every academic year. Since the MP's quota facilitates admissions over and above the KVs' class strength, it inflates the class strength and thereby distorts the Pupil-Teacher Ratio.

Maintaining a healthy pupil-teacher ratio, especially at foundational learning levels is critical to ensure the realisation of desired learning objectives.This has been reiterated by the New Education Policy 2020 which recommends a ratio below 30:1 for schools and anchors an aspirational target of below 25:1 for areas with large numbers of socio-economically disadvantaged students. The MP's quota hinders these objectives as it dilutes educational standards in Kendriya Vidyalayas.

The MP quota is an anachronism regrettably surviving in today's India and must be dispensed with at the earliest. Initially conceptualized as a means of enhancing democracy by empowering political representatives to exercise this discretionary power, the MP quota has served little purpose to that end. Such a discretionary provision in admission practices discounts quality and goes against the very spirit of transparency, consistency, and meritocracy.

Admissions through an exclusive quota is hardly a transparent exercise and whether a political figure has adequately considered the merits before the allotment, is an open contention. A discretion accorded to an elected representative is on the premise of trust by the people that the politician would ascertain its best use. A Member of Parliament is approached by people in numbers many times more than the allotted quota. Evaluating each of the proposals to determine the most deserving and meritorious ones is practically infeasible without any fixed parameter. Therefore, the usage of this power is susceptible to arbitrary and irrational use of discretion. The 7880 seats lying restricted under the MP quota could have been better availed of by deserving and meritorious students in a transparent manner.

Moreover, even after selecting the ten students as per the limit, an MP is forced to turn down a huge number of proposals. This constraint provokes public anger in the

constituency as a multitude of people gets rejected without any definite rational basis. As also evinced by the experiences of many other fellow parliamentarians, in practice, this quota has become an unpopular power with MPs and one which has overstayed its welcome.

Allotment of seats under the MP quota is also an inconsistent practice if one looks at the other central educational institutions of the country. There exists no such exclusive quota for MPs in Jawahar Navodaya Vidyalayas or for that matter other central universities and institutes in India. Hence, it goes against reason to have this provision exclusively for Kendriya Vidyalayas. When, as a matter of fact, parliamentarians have not been provided with any jurisdiction in the form of exclusive recommendation quotas over other central educational institutions, doing it for KVs is an aberration.

And lest one may be tempted to think that these are merely some ideal principles which the MP Quota falls short of, this quota also undermines a constitutional provision in a flagrant disregard of reservations. The quota is manifestly perverse in the sense that admissions through it fail to maintain fidelity to the constitutionally mandated 50% reservation criteria for SC, ST and OBC. Moreover, it has also been depriving Economically Weaker Sections' right to 10% reservation and ignored the right of the differently-abled students to 3% horizontal reservation.

Bereft of any allegiance towards reservation policy, this quota has been denying and depriving about 3940 students of their constitutional right, every year in its existence. As a consequence, the quota undermined one of the envisaged causes of establishing KVs in the country: providing admissions to students hailing from marginalized communities and disadvantaged sections of India. Hence, abolishing the quota will be a welcome step towards

respecting the constitutional provision and the cause of establishing Kendriya Vidyalayas.

As our democracy matured, we have done away with many discretionary powers of political figures in the past to minimize arbitrariness in their exercise: from the abolishment of gas pumps to appointments and nomination powers of various ministers as recommended by Group of Ministers in 2011.

Even the union education minister's discretionary quota for admissions was scrapped recently. Admissions through it had surged a staggering 27 times from 450 to 12295 in 2020-21 until the Union Education Minister surrendered this quota as a result of which no further admission under the Minister's discretionary quota has taken place thence.

Keeping with the thrust of developments, it is, therefore, exigent to retire the MP's discretionary quota under the Special Dispensation Admissions Scheme, only this time, settling it once and for all.

Why discretionary quotas in KVs are inherently unfair

(हिन्दुस्तान टाइम्स में दिनांक 31 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित मेरा लेख)

In a recent development, admissions through special provisions schemes have been held in abeyance by the Kendriya Vidyalaya Sangathan. The decision to stop admissions through various quotas, although ad interim, was an expected upshot of the animated discussions on the issue in the recently concluded Budget Session. While this evinces welcome progress of the governments' deliberations on the controversy, a decisive stance remains pending.

Admissions under the special schemes comprise 21 distinct quota categories of which 2, namely the MP quota and the Sponsoring Authority Quota, provokes concern. Both allow admissions over and above the class strength of KVs and have an unaccountable discretionary element.

Every MP has a quota to recommend 10 admissions to KVs. Additionally, there's a quota of at least 17 seats per KV with the sponsoring authorities, exercised mostly by the District Collector. Thus, across the 1248 KVs, 30,000 odd seats remain restricted every year to serve the discretionary powers of MPs and DCs.

As India celebrates Ambedkar's 131st birth anniversary, the suspension is pertinent because the quota has been a blemish on his espoused principles of social justice and inclusion. It has continued despite a flagrant disregard of constitutionally mandated reservations and has been denying marginalised and socially disadvantaged students their right to reservations.

In 2021-22, of the 7301 admissions under MP quota, a paltry 8.34% went to SCs and 2.9% to STs, which is less than half of the constitutional provision of 15% and 7.5% accorded to SCs and STs respectively. Without any allegiance to reservation policy, the quota also ignores the right of the differently-abled students to 3% horizontal reservation.

Beyond delivering a mere utilitarian goal of education, government schools like KVs facilitate an institutional setting for social inclusion. It is essential that they embrace constitutional principles of reservations and are free from arbitrariness in admissions. Time and again, the issue has arisen in parliamentary parlance as legislators and judiciaries have wavered over the quota's validity. Amid the recent salvos of competing views, it is opportune to reassess the relevance of such special admissions.

With over 14 lakh students benefiting from these subsidised schools, the ethos of meritocracy is imperative to sustain their stellar quality. Discretionary quotas bring in distortions as they are not governed by fair considerations for merit. Such powers are an anachronism in today's India and hardly square with democratic principles.

The debate straddles two views. One side seeks the enhancement of the quota because the seats allotted to an MP is insignificant and falls short of reasonably meeting the demands of a populous constituency.

On the other side, parliamentarians demand the outright scrapping of the quota, citing the infeasibility of exercising this power with fairness.

The clamour for enhancing the quota acknowledges the problem correctly that the allotted number serves almost no purpose, but is misguided in remedying it. The historical trajectory of the MP quota reflects the systemic flaw inherent in it. Not with standing three abolishment, including a High Court strike-down, the quota has been increased thrice since its inception: from 2 to 5 in 2011, from 5 to 6 in 2012 and then from 6 to 10 in 2016. Yet the problematic issues have persisted.

An MP gets a barrage of admissions requests, often at least an order of magnitude higher than the allotted quota. As the quota increased, so did the number of contenders, but disproportionately. Enhancing it further will exacerbate the

issue of inciting public dissatisfaction as legislators will be flooded with even more requests, which they would be anyway forced to turn down.

It's high time such discretionary quotas for admissions in KVs are retired, once and for all. Prone to random choice or personal whims, their exercise has been un constitutional and discounted both merit and transparency.

It is practically infeasible for an MP to comprehensively evaluate every request and select the most deserving ones. In a democracy, people accord power to representatives on the premise that the person shall ascertain its best use. Whether an MP or a Sponsoring Authority has exercised the discretion after adequately assessing each of the multitude of cases is an open contention and therefore gets a lot of flak including allegations of corruption.

It's tempting to retain power to exercise discretion especially when it allows for doling out favours to people in a constituency. May be that explains the quota's continued persistence despite its erratic history. But the fact that we have successfully abolished many discretionary powers in the past, augurs hope. Even the union education minister has relinquished his quota in KVs when admissions through it inflated 27 times to 12295 from the recommended limit of 450.

The current suspension is welcome, but a revision of the relevance of each of the 21 quota categories and the permanent scrap page of the above-discussed 2 quotas will be apposite to the times.

For a United States of GST

(इकोनोमिक टाइम्स में दिनांक 31 मई, 2022 को प्रकाशित मेरा लेख)

Even as the fifth anniversary of GST approaches, the States are beginning to worry on the likely impact on their finances. With the era of assured revenue set to come to a close on the 30th of June, 2022 such worries are not misplaced. However, GST being a co-operative enterprise of the Union and the States, the Centre too must be equally concerned, for the Centre cannot be strong unless the States do well on the fiscal front.

Under the GST States were guaranteed, for the first five years of GST, to be compensated any revenue shortfall calculated by assuming a 14% annual y-o-y growth over the base year sub-sumed revenue for 2015-16

The compensation amount was not to be paid from the Consolidated Fund of India but from the compensation Fund created through levying cess over and above the GST on supplies attracting the highest GST rate of 28% basicallyon luxury, demerit and sin goods viz pan masala, aerated drinks, coal, tobacco, automobiles.

According to RBI study of state finances, the average growth rate in collection from subsumed taxes during the 3 years' immediately preceding GST stood at 8.9% for the 18 major non special category states but states in the GST council, negotiated a 14% CAGR over seven years. GoI also agreed this high growth of 14% assuming that GDP growth rate too would be on the higher side.

GST was doing well till the pandemic hit during 2019-20.The GST revenue, despite a sudden drop in March 2020, had a shortfall of just 9970 crores. Thus it is clear that there was very little problem during the first 3 years of GST until the onset of the pandemic.

GST, thus, was just beginning to unleash its potential when the pandemic struck. It has not recovered since even though it

is on the rebound, thanks to the slew of measures undertaken by the Government during the last year.

From April 2020 to June 2022 the shortfall from the 14% benchmark was projected at Rs- 6.72 lakh crores. Cess revenue during the said period was expected to fall far short of the requirement thus entailing a large gap.

It was in this backdrop that the GST Council decided to resort to borrowings (to finance a part of the compensation gap) and to extend the levy of cess till March, 2026. The entire shortfall, however, was not borrowed and the gap only to the extent of 7% growth was funded through the borrowing route, thereby leaving arrears of compensation. Accordingly, Rs.1.1 lakh crores and Rs.1.59 lakh crores was borrowed during 2020-21 and 2021-22 respectively. It was decided that the cess collected during the extended period would be used for debt servicing and paying arrears of compensation.

Further, the collection from cess during the period April, 2020 to March, 2026 was projected at Rs.6.61 lakh crores. The amount required for debt servicing being of the order of Rs.3.3 lakh crores and the arrears of compensation being of the same order, almost the entire cess collected from the extended period would go to liquidate the debt and pay off arrears of compensation.

Many states have requested for extension of the compensation. Ignoring the fact that the period of levy has already been extended till March, 2026 and whatever cess is collected in the extended period will be used for debt servicing and arrears payment. There is very little scope for widening the levy of the cess; further revising the cess rates is also not a viable options since the levy of cess has already reached saturation level and any further hike may well prove counterproductive.

However, the States will find it difficult to live down the 14% growth scenario that they will have experienced with GST. The States are staring at a gap of almost Rs.1 lakh crores on

this count during the current fiscal year on cash basis. A gap of this order is likely to continue in the absence of sustained tax effort.

This is where the Council will have to apply itself since the options are limited, especially in the wake of the overall global economic order, the Ukraine crisis and the galloping crude prices.

Any major overhaul of the GST rate path may not be feasible, more so in view of the fact that the economy is just beginning to pick itself up and what can be attempted at most seems to be minor tinkering and tweaking here and there.

What can be done, though, is to undertake a review of the exemptions which will help widen the tax base and also enable flow of credit. Rate rationalizations may also be undertaken to remove impediments to domestic industry.

However, the most significant step that the Council can take for this purpose is to streamline the tax administration process to further plug the leakages. Accordingly, audit and scrutiny of returns on the basis of risk analysis is bound to yield dividends. Further controls and validations in the registration regime may be built to prevent fraudsters from entering the system. The return process may further be streamlined to ensure payment on account of liability admitted and prevent tax credit misuse and frauds.

The aforesaid measures are bound to have a salutary effect on the compliance environment and this will shore up the revenue.

Thus, the fifth anniversary of GST may well usher in attempts to consolidate the gains and strengthen the GST ecosystem.

शून्य काल

Demand For Investigation of Cases of Bank Fraud Amounting To Rs. 13,000 Crore

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : सभापति महोदय, इस समय देश के अंदर बैंक फ्रॉड के सौ से ज्यादा केसेज पेन्डिंग हैं for lack of consent with different State Governments, amounting to Rs. 50,000 crore. ये चीटिंग, फॉर्जरी, मिसएप्रोप्रिशन और बैंक फ्रॉड के केसेज़ हैं, राज्य सरकारें इन केसेज़ के इन्वेस्टिगेशन की अनुमति प्रदान नहीं कर रही हैं। 'येस बैंक' के 3,664 करोड़ रूपये के पाँच केसेज़ पिछले एक साल से पेन्डिंग हैं। इसमें ILFS के. ट्रांसपोर्टेशन वर्क्स, ILFS के. मेरिटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी डेवलपमेंट तथा राणा कपूर, जो 'येस बैंक' के सीईओ थे, के 1353 करोड़ रूपये और 225 करोड़ रूपये के केसेज़ पेन्डिंग है। येस बैंक ने पाँच केसेज़ रिकमंड किये हैं for investigation which amounts to Rs. 3,664 crores and the cases are pending for investigation for the last one-and-a-half years.

उसी प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 3,046 करोड़ रूपये के केसेज़ पेन्डिंग हैं। डी.एस कुलकर्णी डेवलपर्स 433 करोड़ रूपये, कॉक्स एंड किंग्स लि. 624 करोड़ रूपये और जेट एयरवेज़ के 1,987 करोड़ के केसेज़ पेन्डिंग हैं। उसी प्रकार से यूनियन बैंक के कॉरपोरेट पावर लिमिटेड, जिसके मालिक श्री मनोज जायसवाल हैं, इनका 4,037.87 करोड़ रूपये का केस पेन्डिंग है और सिक्किम फेरो अलॉयज लिमिटेड के 448 करोड़ रूपये और पीएनबी के वदराज सीमेन्ट लिमिटेड और ईएमआई ट्रांसमिशन लिमिटेड के 739 करोड़ रूपये के केसेज़ पेन्डिंग हैं। महोदय, केवल एक शहर मुम्बई में 13 हजार करोड़ से ज्यादा के बैंक फ्रॉड के केसेज़ एक साल से पेन्डिंग हैं।

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई को bank fraud के केसेज़ की जाँच करने के लिए consent नहीं दे रही है। ..... (व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN : No slogans and no comments please.

श्री सुशील कुमार मोदी : सभापति महोदय, अगर देश के सभी राज्यों को

लिया जाए, तो this amounts to more than Rs. 50,000 crores. .. (Interruptions)...

Dr. Fauzia Khan (Maharashtra) : Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

प्रश्न-काल में पूछा गया पूरक प्रश्न

श्री उप सभापति : माननीय सुशील कुमार मोदी जी।

श्री सुशील कुमार मोदी : उप सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि you have mentioned in your reply that the final complaint was filed on 14.12.2020- मैं फिर से दोहराता हूँ - दिनांक 14.12.2020 को एसबीआई ने फाइनल कम्प्लेंट फाइल किया, तो फिर सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने में 12-14 महीनें क्यों लगे? क्या यह बात सही है कि कुछ राज्य सरकारें, जिन्होंने consent withdraw कर लिया था, उनके consent withdrawal के कारण उन राज्य सरकारों ने consent देने में देरी की, जिसके कारण एफआईआर दर्ज करने में 14 महीने लगे? मैं जानता चाहता हूँ कि वे कौन-कौन से राज्य सरकारें हैं, जिन्होंने consent देने में देरी की और जिसके कारण एफआईआर लॉज करने में इतना समय लगा?

श्री उप सभापति : समय कम है। Please answer it briefly.

डॉ. भागवत किशनराव कराड : माननीय उपसभापति महोदय, मैंने आंसर देते समय ही यह बताया है कि जब सीबीआई इंक्वायरी होती थी, तब वहाँ जाकर उनकी इंक्वायरी करनी पड़ती थी। उस समय कुछ राज्यों ने वहाँ जाकर consent देने की power withdraw की थी। उस टाइम सीबीआई को हर राज्य में जाकर परमिशन लेनी पड़ी और उसी में डिले हो गया। That is one of the important reasons for delay in the inquiry.

श्री सुशील कुमार मोदी : वे कौन-कौन से राज्य थे? .... (व्यवधान)...

डॉ. भागवत किशनराव कराड : नम्बर एक, महाराष्ट्र राज्य है तथा दो-तीन अन्य राज्य हैं, जिनके बारे में मैं बताऊँगा। ...(व्यवधान)....

Special Mentions के तहत उठाया गया मुद्दा

Demand For 'One Nation, One Tariff' For Power In India

Shri Sushil Kumar Modi (BIHAR) : Sir, Bihar lacks both coal and other renewable energy resources, which are essential for producing energy. Hence Bihar has to rely on external sources to meet its energy demand.

Over three-fourth of the energy is bought from Central Power Generation companies whose prices are higher than independent power producers. Bihar is thus compelled to purchase power at higher rates which have risen 27 per cent between 2015 and 2020.

Bihar's average power purchase cost is Rs. 5.05 per unit whereas neighbouring Jharkhand is Rs. 4.19 and Odisha Rs. 3.01 per unit. It becomes more pronounced when compared with power-producing States like Gujarat, Punjab and Maharashtra.

This higher purchase cost of power contributes 80-85 per cent of total costs of distribution companies and translates into higher retail tariffs. As a result, electricity tariffs faced by common people in Bihar are higher than neighbouring States. I, therefore, urge the Government of India to bring in 'One Nation, One Tariff' policy to ensure uniform power costs and tariffs across States.

This mechanism can be executed feasibly similar to GST wherein, as a first step, a national fund, pooling the purchase of all generated power and then allocating to States, can be created. It shall normalize costs. This is critical to eliminate undue regional disadvantages and provide level-playing field for power companies.

India is already advancing along this direction through 'One Nation, One Tax' 'One Nation, One Grid' I urge the Government of India to do the same for power tariffs. Thank you, Sir.

Dr. Vikas Mahatme (MAHARASHTRA) : Sir, I would like to associate myself with the Special Mention made by the hon'. Member.

Dr. Amar Patnaik (ODISHA) : Sir, I would also like to associate my self with the Special Mention made by the hon'. Member.

Shri Abir Ranjan Biswas (WEST BENGAL) : Sir, I would also like to associate myself with the Special mention made by the hon. Member.

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

शून्य-काल

रेलवे के ग्रुप 'डी' और NTPC परीक्षार्थियों से जुड़ा मुद्दा

शून्य-काल में उठाया गया मुद्दा

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : मेरा मंत्रालय को यह सुझाव है कि ग्रुप 'डी' का एग्ज़ाम जिसमें more than one crore twenty five lakh students are there, पहले एक एग्ज़ाम अनाउंस किया गया था, all of a sudden, on 24th January, it was announced that there will be two exams. मेरा आग्रह है कि एक एग्ज़ाम ग्रुप 'डी' का एक exams होना चाहिए। There is no requirement of two exams. They are not IAS or IPS exams. टेन्थ क्लास के बच्चों की पहली डिमांड है कि ग्रुप 'डी' के लिए, instead of two exams. there should be one exams, as was announced earlier. (व्यवधान) एक मिनट और, सर। रिगार्डिंग एन.टी.पी.सी., जो 35,000 सीट्स हैं, उसके 3.5 लाख रिजल्ट्स और अनाउंस किए जाने चाहिए। One student one result should be there, एक स्टूडेंट का तीन जगह नाम है, इसलिए जो 7 लाख रिज़ल्ट्स अनाउंस किए हैं, it is actually only 3,50,000. So, I appeal to the Railway Ministry to announce another 3,50,000 results of the students so that they can appear in the exam. इसलिए मेरा आग्रह है कि बिना कमेटी की रिपोर्ट का इन्तजार किए, सरकार को निर्णय लेना चाहिए।

MR. Chairman : Thank you. Shri Sanjay Singh to associate.

Dr. Amee Yajnik (GUJARAT) : Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. member.

Shrimati Priyanka Chaturvedi (MAHARASHTRA) : Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. member.

Shri Kanakamedala Ravindra Kumar (ANDHRA PRADESH): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Shri M. Mohamed Abdulla (TAMIL NADU) : Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Dr. Sasmit Patra (ODISHA) : Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Dr. Amar Patnaik (ODISHA) : Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

प्रश्न–काल में पूछा गया पूरक प्रश्न

श्रीमती छाया वर्मा : मेरा दूसरा सवाल यह है कि रेलवे ने पिछले पाँच वर्षों में कितने पदों को समाप्त किया है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : उप सभापति महोदय, रेल विभाग में भर्ती का आयोजन करना एक निरंतर प्रक्रिया है। रेलवे में जो भर्ती होती है, उस भर्ती के सात नोटिफिकेशंस निकले थे। उसके फर्स्ट फेज में 1,43,034 उम्मीदवारों की भर्ती पूर्ण रूप से हुई और सेकेंड फेज में 1,40,713 उम्मीदवारों की भर्ती पूरी हुई है। इस तरह से टोटल 2,83,747 उम्मीदवारों की भर्ती हुई है और भर्ती की कुछ प्रक्रिया अभी भी चालू है। 2,00,758 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी दे दिये हैं, जिसमें आरपीएफ और आरपीएसएफ भी शामिल है।

श्री सुशील कुमार मोदी : उप सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय रेल मंत्री, श्री अश्वनी वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके प्रयास से आन्दोलनरत रेलवे परिक्षार्थियों की सारी माँगों को मान लिया है। उन्होंने यह एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं माननीय मंत्री जी से एक आग्रह करूंगा कि ग्रुप-डी की जो परीक्षा स्थगित कर दी गई थी, उसे शीध्रताशीध्र कराने का कष्ट करें। आपने जुलाई में परीक्षा आयोजित कराने का एलान किया है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इसमें पहले ही दो-तीन साल का विलम्ब हो चुका है, क्या सरकार यह बता सकती है कि परीक्षा कब आयोजित की जा सकेगी?

श्री दानवे रावसाहेब दादराव : महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह बात सही है कि छात्रों की जो माँगें थीं, वे पूरी कर दी गई हैं, लेकिन मैं

माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि एक उम्मीदवार के एक से ज्यादा कैटेगरी में उत्तीर्ण होने के कारण जो परसेप्शन निर्मित हुआ है, उसके हल के लिए आरआरबी ने उस उम्मीदवार के हक को अबाधित रखते हुए वह उम्मीदवार केवल एक ही पोस्ट की उम्मीदवारी स्वीकार करे, ताकि बाकी जगह के अगेन्स्ट और ज्यादा नये उम्मीदवार को दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जा सके। इस कारण किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा और जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित करके उन्हें न्याय दिया जाएगा।

Dr. Chairman: Shri Sushil Kumar Modi to associate-

शून्य काल

Demand For Timely Local Body Elections With Reservations For OBCs

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : सभापति महोदय, पिछले 50 वर्षों से देश के अधिकांश राज्यों में Other Backward Classes की लिस्ट बनी हुई है और उसी OBC की लिस्ट के आधार पर एजुकेशन और जॉब्स में रिज़र्वेशन मिलता है। जब 73rd और 74th amendments हुए, तो पंचायत और urban local bodies में भी उसी OBC की लिस्ट के आधार पर आरक्षण दिया जाने लगा, लेकिन हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एजुकेशन और जॉब की लिस्ट अलग होगी तथा पोलिटिकल रिज़र्वेशन की लिस्ट अलग होगी। इसका परिणाम यह हुआ है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पंचायत और urban local bodies के चुनावों को स्थगित करना पड़ा है। कर्णाटक और बिहार में भी चुनाव कराना मुश्किल हो गया है, क्योकि पॉलिटिकल रिज़र्वेशन की अलग लिस्ट बनाना बहुत ही कठिन काम है। कोर्ट ने कहा है कि एक dedicated Commission बनाइए to conduct a rigorous empirical enquiry in to the nature and implications of backwardness qua local bodies, within the State. राज्यों के पास कोई empirical data नहीं हैं कोर्ट ने यह भी कहा है कि हर लोकल बॉडी का रिज़र्वेशन अलग होगा और हर लोकल बॉडी की लिस्ट भी अलग होगी।

सभापति महोदय, यह काम बहुत ही कठीन है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिना triple test के आप इलेक्शन नहीं करा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि dereserve OBC seats in all future local bodies till seperate list on the basis of triple test is prepared for political reservation.

मैं आग्रह करूँगा कि जिस तरह से SC/ST के लिए एक ही लिस्ट है, जिसके आधार पर एजुकेशन, जॉब तथा पॉलिटिकल रिज़र्वेशन मिलता है, उसी प्रकार ओबीसी के लिए भी एक ही लिस्ट के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। इसके लिए अगर आवश्यक हो, तो कानून बनाया जाना चाहिए।

Special Mentions के अन्तर्गत उठाया गया मुद्दा

Demand For Evolving National Policy To Facilitate Retail Traders

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : उप सभाध्यक्ष महोदय, इस देश में खुदरा दुकानदारों, व्यवसायियों की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा है जो सकल घरेलू उत्पाद में 12 प्रतिशत का योगदान करते हैं। करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। इन खुदरा दुकानदारों को व्यवसाय प्रारंभ करने और चलाने हेतु दर्जनों कानून, परमिट, लाइसेंस, अनुपालन की आवश्यकता पड़ती है।

इन खुदरा दुकानदारों को जहाँ एक ओर ई-कॉमर्स कंपनियों से मुकाबला करना पड़ रहा है, वही दूसरी और बैंकों से सस्ता ऋण, भण्डारण, मालों की आवाजाही में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना, मुत्यु, दुकान में चोरी या आग लगने से किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है।

खुदरा दुकानदारों एवं अन्य व्यापारियों की समस्याओं पर सरकार को सुझाव देने हेतु 26 जुलाई, 2019 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड' के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी, परन्तु अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है।

अतः मैं सरकार से माँग करता हूँ कि देशव्यापी 'खुदरा व्यापार नीति' एवं सुरक्षा बीमा योजना' लागू की जाए तथा 'राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड' का गठन किया जाए।

शून्य काल

Demand For High Level Inquiry To Investigate Atrocities Against Pandits In Kashmir

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : सभापति महोदय, वर्ष 1989 से 1998 के दौरान 700 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई। ...(व्यवधान).. उनकी सम्पत्ति पर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया गया। ...(व्यवधान)... तीन लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। ...(व्यवधान)... It was an ethnic cleansing; it was genocide; it was a holocaust. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN : This sort of disturbance will undermine the privilege and prestige of the House. ...(interruptions)... Please go to your seats. ... (interruptions)... You know that I will not be accepting it. ....(interruptions)...

श्री सुशील कुमार मोदी : सभापति महोदय, 1998 में वंधामा में 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई। वहाँ पीएम श्री आई.के. गुजराल भी गए थे। ...(व्यवधान)... 1997 में सात कश्मीरी पंडितों की संग्रामपुर में हत्या कर दी गई।...(व्यवधान)... वर्ष 2003 में नदीमर्ग में 24 पंडितों की हत्या कर दी गई। ...(व्यवधान).... सभापति महोदय, मकबूल भट्ट को फाँसी की सज़ा देनेवाले रिटायर्ड सेशन जज, नीलकंठ गंजू की वर्ष 1989 में हत्या कर दी गई। ...(व्यवधान) .. इसी प्रकार, इंडियन एयर फोर्स के चार लोगों की हत्या कर दी गई। ...(व्यवधान) ... गिरिजा टिक्कू, टीका लाल टपलू, दूरदर्शन कश्मीर के डायरेक्टर लस्सा कौल, सर्वानन्द कौल प्रेमी, भूषण लाल रैना, इस सबकी भी हत्या कर दी गई। ...(व्यवधान)... इतना ही नहीं, गिरिजा टिक्कू की बलात्कार के बाद आरा मशीन में काटकर हत्या कर दी गई। ...(व्यवधान)...

सभापति महोदय, 32 साल हो गए, लेकिन कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं मिला है। ....(व्यवधान)... 200 से ज्यादा FIRs दर्ज हुई हैं, लेकिन उनमें से एक भी FIR conviction में परिणत नहीं हुई है। ...(व्यवधान)... मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की

अध्यक्षता में SIT का गठन किया जाए, जो Court monitored हो और जो assisted by CBI, NIA, ED, J&K police हो। ...(व्यवधान)... I demand registration of fresh FIRs, reopening, reinvestigation and speedy disposal of pending charge-sheets. ...(Interruptions)..

इसलिए मैं आपके माध्यम से यह माँग करता हूँ कि तमाम FIRs पर SIT गठित करके उनकी जाँच कराई जाए और 32 साल के बाद जिन दोषियों को सजा नहीं मिली है, ...(व्यवधान) ....

MR. Chairman : Please sit down. ....(Interruptions) ... Please sit down. ..... (interruptions)... Let everybody go to their seats. ...(interruptions) ....

श्री सुशील कुमार मोदी : बिट्टा कराटे और यासीन मलिक जैसे लोग, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ कार्रवाई करने की आगे कोई और हिम्मत न कर सके। .....(व्यवधान) ...

Shri Abir Ranjan Biswas (WEST BENGAL) : Sir, I associate myself with the Zero Hour submission made by the hon'. Member.

Shri Sujeet Kumar (ODISHA) : Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon'. Member.

Shri Kanakamedala Ravindra Kumar (ANDHRA PRADESH) : Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

Dr. Amar Patnaik (ODISHA) : Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon'. Member.

शून्य-काल

Demand For Bringing Crypto Assets Under G.S.T.

Mr. Chairman: Now, Zero Hour, Matters to be raised with permission of Chair; Shri Sushil Kumar Modi. Please take two minutes only.

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : सभापति महोदय, virtual digital asset और crypto पर सरकार ने highest slab of tax, 30 percent लगाया है and that is without any exemption. That is to dissuade people from investing in crypto because it is highly speculative and volatile. The tax treatment is similar to betting but there is no clarity regarding levying of G.S.T. Sir, the Government is levying 18 percent G.S.T. only on service provided by the crypto exchange and is treating it as financial services but cryptos are similar to lottery, casinos, betting, gambling, horse-racing which have 28 percent of G.S.T. and that is also on the entire value, on the entire transaction. Even on the gold, there is G.S.T. on the entire transaction value. Even on the shares, there is a transaction tax on the entire value.

Sir, I urge the Government of India to take initiative in the G.S.T. Council to levy a 28 percent G.S.T. on entire value like lottery, betting, gambling or casinos. It is not an instrument of skill.

MR. CHAIRMAN: Right.

Shri Sushil Kumar Modi : It is an instrument of chance. अगर आवश्यकता हो तो एक्ट में संशोधन किया जाए और नए प्रावधान की व्यवस्था की जाए और यदि आवश्यकता हो तो GoM का भी गठन किया जाए।

Mr. Chairman : Shri B. Lingaiah Yadav. सुशील जी, दो मिनट हो गए हैं।

Shri Sushil Kumar Modi : Sir, fifteen seconds only. This crypto has no ownership. ...(Interruptions)...

Mr. Chairman: One minute, Lingaiah ji.

Shri Sushil Kumar Modi: Nobody knows who the owner of crypto is. There is no intrinsic value, no underlying value. It is neither security, nor commodity; so, it is not an asset and even if it is an asset, it should be treated like gold.

Mr. Chairman: Now, Shri B. Lingaiah Yadav. सुशील कुमार मोदी जी, आपने 15 सेकेंड का समय मांगा था, 15 सेकेंड हो गए हैं।

Dr. Amar Patnaik (ODISHA): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Dr. Fauzia Khan (MAHARASHTRA): Sir, I too associate my self with the issue raised by the hon. Member.

Marital Rape संबंधी पूछा गया पूरक प्रश्न

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : उपसभापति महोदय, अगर marital rape को criminalise कर दिया गया, तो विवाह की संस्था ही समाप्त हो जाएगी और कब पत्नी ने consent दिया और कब withdraw किया – यह प्रूव करना मुश्किल होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस संबंध में कोर्ट में सरकार का क्या पक्ष है? क्या सरकार marital rape को criminalise करने के पक्ष में है या उसको immunity प्रदान करने के पक्ष में है? मेरा यह सुझाव है कि इसको immunity प्रदान किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, तो यह जो विवाह की संस्था ही खत्म हो जाएगी।

Shrimati Smriti Zubin Irani : Sir, the hon. Member has constitutionally served his home State very, very effectively and hence I would be appealing to him to repeat Rule 47. I cannot elaborate on a *sub judice* matter. However, his opinion, I would like to highlight to him for research purposes, finds a reflection in the 172nd Report of the Law Commission and also of the Departmental Standing Committee related to Home Affairs in the year 2013.

Websites पर महिलाओं के अश्लील चित्र डालने से जुड़ा मुद्दा

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि Department of IT has asked the Indian Computer Emergency Response Team to form a high-level Committee to investigate complaints that a few websites had hosted doctored nude pictures and objectionable comments and insulting and auctioning Muslim women? अगर ऐसा है, तो वेबसाइट्स के खिलाफ या ऐसे लोगों के बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

श्री अश्वनी वैष्णव : महोदय, यह बहुत ही संवेदना वाला विषय है और महिलाओं की सुरक्षा, protecting the dignity of women एक fundamental construct है। हम इसमें किसी भी तरीके से कोई compromise नहीं कर सकते हैं।**....**(व्यवधान)**...**उसमें किसी भी religion की बात नहीं है, किसी क्षेत्र की बात नहीं है। यह किसी भी तरीके से हमारा commitment है। अभी तक जितने भी प्वाइंट्स आए हैं, उन सभी प्वाइंट्स पर तुरंत कार्रवाई की गई है। हमारी जानकारी के हिसाब से उस पर आते ही कार्रवाई की गई है।

माननीय उपसभापति जी, मैं एक महत्वपूर्ण विषय इस सदन में रखना चाहूंगा। हम जब भी सरकार की तरफ से social media को accountable बनाने के लिए कोई भी कदम उठाते हैं, तब हमारे विपक्ष के साथी सबसे पहले हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम कहीं न कहीं freedom of speech के ऊपर आघात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सोसायटी में एक बैलेंस लाना ही पड़ेगा, एक consensus लाना ही पड़ेगा कि हमारे नौजवानों, महिलाओं, हमारी बहनों, हमारी बेटियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए जो करना है, उसके लिए social media को accountable करना ही पड़ेगा, उसको अगर सेफ रखना है, तो उनको उन नियमों को और ताकत देनी ही पड़ेगी। उसके लिए अगर आप हमारे ऊपर यह आरोप लगाएंगे कि आप freedom of speech को तोड़ रहे हो, उसको रोक रहे हो, तो वह गलत आरोप है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सभी को मिलकर एक नई दिशा में जाना होगा।

बरौनी खाद कारखाना चालू कराने से जुड़ा मुद्दा

डॉ. मनसुख मांडविया : महोदय, मैं आपको यह भी बता दूँ कि इस साल एक ऐसी स्थिति का निर्माण हो गया था कि Covid crisis की वजह से international market में Phosphoric acid का price बढ़ गया, DAP दुनिया में कहीं मिल नहीं रही थी, ship नहीं मिल रहा था और ऐसी स्थिति में देश में DAP की demand होती थी। जब किसान को खाद की आवश्यकता होती है, तब वह खाद खरीदने के लिए जाता है। वह wait नहीं करता है। जब उसको खाद नहीं मिलती, तो तुरंत ही किसान अपनी बात को रखता है। ऐसी स्थिति में देश में DAP की कमी न रहे, जबकि international price बढ़ गया, तो हमने एक बैग पर 1,650 रूपए की subsidy दी, लेकिन हमने किसानों से ज्यादा पैसा नहीं लिया। हमने देश के किसानों को DAP 1,200 रूपए में ही उपलब्ध कराया। हमने इस साल किसानों के लिए सबसे highest subsidy use की।

श्री उपसभापतिः माननीय सुशील कुमार मोदी जी।

श्री सुशील कुमार मोदीः महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि बिहार में बरौनी के अंदर फर्टिलाइजर कारखाना है, जिसके उद्घाटन की डेट लगातार बढ़ती जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उसमें कब तक उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा, उसका investment कितना है और अब तक कितना खर्च हो चुका है?

डॉ. मनसुख मांडवियाः महोदय, जैसा मेरे राज्य मंत्री ने बताया, 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत देश में ही हमारे देश की requirement के अनुसार खाद का उत्पादन हो, इसलिए हम 5 plants का revival कर रहे हैं। उनमें से रामागुंडम प्लांट already commissioned है, गोरखपुर प्लांट already commissioned है। सिंदरी और बरौनी, दोनों fertilizer plants का काम गति से चल रहा है। बरौनी के संदर्भ में माननीय सदस्य ने जो information माँगी है, 2016 में उसका JV final हुआ था और उसके बाद उसकी project cost 8,388 करोड़ रूपए तय की गई थी। 17, फरवरी

2019 को उसका foundation stone lay किया गया था। मुझे माननीय सदस्य को बताते हुए खुशी हो रही है कि उसकी overall progress अच्छी है और उसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है। covid crisis की वजह से वह थोड़ी सी लेट हुई है, यह 6-7 महीने लेट हुई है, लेकिन हमने आज 95 परसेंट काम पूरा कर दिया है और जून, 2022 में हम उसको commission करके dedicated to nation कर देंगे।

माँ जानकी के जन्म स्थान पुनौरा धाम से जुड़ा मुद्दा

श्री प्रहलाद सिंह पटेलः माननीय उपसभापति जी, बिहार को पर्याप्त मात्रा में 'स्वदेश दर्शन' और प्रशाद' योजना का लाभ मिल रहा है। हमारे जितने भी परिपथ हैं, उनमें चाहे बौद्ध परिपथ हो, चाहे गाँधी जी के नाम पर ग्रामीण परिपथ हो, सबके लिए धनराशि दी गई है। बिहार की एक बड़ी पुरानी मांग रही है, जो पुनौरा धाम, सीतामढ़ी है, इसको 'प्रशाद'' योजना में ले लिया गया है। दूसरी मांग ग्रामीण परिपथ थीम के तहत भितिहरवा - चंद्राहिया - तुर्कोलिया की रही है, जो गाँधी परिपथ था। इसकी भी बड़ी डिमांड रही है। लगातार बौद्ध धर्मावलम्बियों का पर्यटक के रूप में पर्याप्त मात्रा में वहां पर आगमन है। अभी कुशीनगर हवाई अड्डा के बनने के बाद से मुझे लगता है कि वहां पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी।

जहाँ तक माननीय सदस्य ने अपने सवाल में स्थानों के नाम लिए हैं, वे महत्वपूर्ण स्थान हैं और दुनिया के मानचित्र पर उनकी पहचान भी है।

श्री उपसभापति : माननीय सुशील कुमार मोदी जी।

श्री सुशील कुमार मोदी : उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि माँ जानकी के जन्म स्थान पुनौरा धाम को 'प्रशाद' योजना में शामिल किया गया है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि जो पी.एम. पैकेज घोषित किया गया था, उसमें बिहार के पर्यटन के लिए 500 करोड़ रूपये का प्रावधान था। अभी माननीय मंत्री जी ने जो जबाव दिया है, उसे देखकर मुझे लगता है कि यह 250 करोड़ रूपये के आस-पास है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पी.एम. पैकेज की जो 500 करोड़ रूपये की घोषणा थी, उसमें से बाकी बची राशि को देने के बारे में सरकार का क्या विचार है?

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : उपसभापति महोदय, पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय को मिलाकर अगर मैं कहूँगा, तो वह संख्या 500 करोड़ रूपये से ज्यादा हो जाती है। मगर राज्य सरकारें जो प्रस्ताव भेजती हैं, उसके बाद ही भारत सरकार अपनी योजनाओं के तहत उसमें पैसा देती है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि चाहे 'स्वदेश दर्शन' हो, चाहे 'प्रशाद' हो, चाहे कार्यक्रम के आयोजन की जितनी भी हमारी योजनाएँ हैं, बिहार को सभी योजनाओं को अंतर्गत पैसा दिया गया है। जैसा कि अभी मैंने अपने उत्तर में कहा था कि जो बड़ी मांग थी - अन्य ऐसा कोई भी प्रस्ताव अगर राज्य सरकार से आएगा, तो केन्द्र सरकार उस पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी ।

भारत में बाघों की मृत्यु से जुड़ा मुद्दा

श्री सुशील कुमार मोदी : माननीय उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर में जो आँकड़े दिए हैं, उनमें बताया है कि मध्य प्रदेश में 2019 में 31 टाइगर्स की डेथ हुई, 2020 में 29 की डेथ हुई और 2021 में 42 टाइगर्स की डेथ हुई। उत्तर में मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में टाइगर्स के मरने की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। 2019 में पूरे देश में 96 टाइगर्स की डेथ हुई थी, 2020 में 106 टाइगर्स की डेथ हुई and that was increased to 127 in the year 2020-21. मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि लगातार टाइगर्स की डेथ की संख्या बढ़ रही है, क्या इसका कोई खास कारण है?

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय उपसभापति महोदय, टाइगर्स की जो डेथ हैं, उसके अलग-अलग कारण हैं और इसमें ओल्ड एज एक बड़ा कारण है। टाइगर्स के अंदर आपस में भी जो infighting रहती है, वह भी एक कारण है। कुछ जगह linear projects के कारण....(व्यवधान)... जी हां, यह सब जगह है। कुछ जगह पर electrification के कारण भी इनकी डेथ हो जाती है, poaching भी इसका कारण है और disease भी एक कारण है। जहाँ तक poaching या linear projects का सवाल है, सरकार के द्वारा उसके लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र यादव (क्रमागत) : जो ओल्ड एज है, वह भी एक कारण है, लेकिन सभी विषयों का मंत्रालय के द्वारा संज्ञान लिया जाता है। इसलिए हमने पूरी संख्या इस प्रश्न के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत की है।

श्री सुशील कुमार मोदी : महोदय, एन.टी.सी.ए. की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसके अनुसार fifty per cent fell prey to poachers. यानी नॉर्मल डेथ तो समझ में आती है, लेकिन 50 परसेन्ट से ज्यादा डेथ्स पोचिंग के कारण हुई हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पोचिंग को रोकने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार क्या प्रयास कर रही है, ताकि पोचिंग से होने वाली टाइगर्स की मौत को रोका जा सके।

श्री भूपेन्द्र यादव : उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि 2018 की एनटीसीए की रिपोर्ट हमने प्रकाशित की, उसमें सेंट पीटर्सबर्ग में पूरी दुनिया के सामने टाइगर्स की संख्या बढ़ाने के लिए जो समझौता किया गया था, भारत उन चुनिंदा देशों में है, जिन्होंने अपने यहाँ इनकी संख्या दोगुनी की है और हमारे यहाँ टाइगर्स की संख्या बढ़ी भी है। लेकिन माननीय सदस्य के द्वारा जो पोचिंग का विषय उठाया गया है, उस पर मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो है, उसके संबंध में वह कठोर कदम उठा रहा है और उस संस्था को स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। जो एनटीसीए की सालाना बैठक होती है, पिछले महीने ही हमारी गवर्निंग बॉडी की वह बैठक हुई है और उसमें भी हम लोगों ने तय किया है जितने भी टाइगर्स रिज़र्व एरियाज़ हैं, वहां के जो डायरेक्टर्स है, उन्हें हमने एक स्पेशल डायरेक्शन दी है कि विशेष रूप से पोचिंग को लेकर, प्रोजेक्ट्स को लेकर और इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर जो समस्याएँ आती हैं, उसके संबंध में अपनी एक comprehensive report भेजें। हम उस रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में उस पर उचित कार्रवाई भी करेंगे।

The world is seeing India with a ray of hope and our diaspora can play a crucial role in further spreading it. The Indian community does not settle abroad to enter into politics or take a seat in the global politics. Wherever they go, they think and act towards benefit of the society.

- Narendra Modi

हम अपने संसाधनों, कौशल और उद्यम की ताकत पर स्वाभाविक रूप से अपने लक्ष्यों का पीछा करेंगे। लेकिन, हम जानते हैं कि जब हम दुनिया के साथ भागीदारी में ऐसा करते हैं तो हम और अधिक सफल होंगे.

सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो
सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो
इधर उधर कई मंज़िले हैं, चल सको तो चलो
बने बनाये है साँचें जो, ढ़ल सको तो चलो

किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं
तुम अपने आप को
खुद ही बदल सको तो चलो

यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता
मुझे गिराके अगर तुम
संभल सको तो चलो

यही है जिन्दगी कुछ चन्द उम्मीदें
इन्ही खिलौनो से तुम भी बहल सके तो चलो

-नरेन्द्र मोदी